twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

In Just 500 ₹
Get
Video AD +2 Days Free Marketing
Advertise On Leading News Channel
9891255609
9354173558
9891221238

DD दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शनिवार, 29 मार्च, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 143, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

केंद्र सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

1 करोड़ 15 लाख लोगों को होगा फायदा, विनिर्माण योजना को मिली मंजूरी

नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन अथवा पेंशन के 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ती है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फामूर्ले के अनुसार है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। केन्द्र सरकार ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को जोड़ने को मंजूरी प्रदान की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किए जाने को मंजूरी प्रदान की है।

किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रुपये में मिलेगी

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025 तक किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी सम्बन्धी कैबिनेट के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी की बोरी 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलेगी। कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है।

कैबिनेट: इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी

नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को 22,919 करोड़ फंड के साथ मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि योजना इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र में बड़े निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन करने तथा 91,600 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार तथा अनेक अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

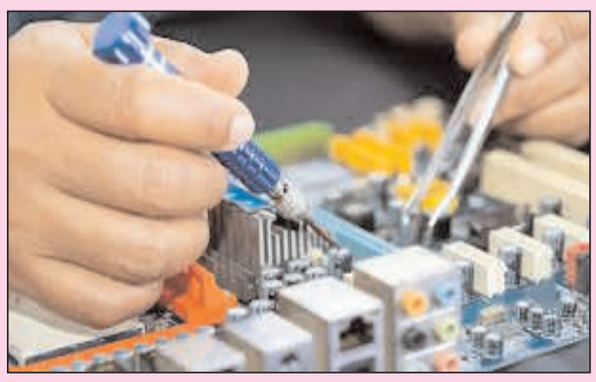

यह योजना भारतीय निमार्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना छह वर्ष के लिए है। इसे एक साल बढ़ाया जा सकता है। प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान रोजगार लक्ष्य उपलब्धि के साथ जुड़ा हुआ है।

पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी

नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने चार लेन के पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एएएम) से बनने वाले 120.10 किमी लम्बे कॉरिडोर पर 3,712.40 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्र की आर्थिक मामलों (सीसीईए) की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्माण को आज मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री वैष्णव ने बताया कि पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इससे लखनऊ, पटना, रांची और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वर्तमान में सासाराम, आरा और पटना के बीच कनेक्टिविटी मौजूदा राज्य राजमार्गों (एसएच2, 12, 81 और 102) पर निर्भर है और आरा शहर में भारी भीड़ के चलते 3-4 घंटे लगते हैं। एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मौजूदा ब्राउनफील्ड हाइवे के 10.6 किमी के उन्नयन के साथ बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए विकसित किया जाएगा। इससे घनी आबादी वाले आरा, गड़हनी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम की जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना को प्रमुख परिवहन गलियारों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें एनएच-19, 319 922, 131जी और 1220 शामिल हैं। इससे औरंगाबाद, कैमूर और पटना को जोड़ेंगे।

जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को मंजूरी

नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रधारी सिंह और उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। दिल्ली स्थित अपने आवास से अधजले नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा विवादों में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम के इस फैसले के खिलाफ 27 मार्च को देश के कुछ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के सदस्य जजों से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। राष्ट्रपति के ताजा आदेश के पहले जस्टिस यशवंत वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां वापस ले ली गयी थीं। जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट की 14 प्रशासनिक कमेटियों के सदस्य थे।

ईद पर खुले रहेंगे एलआईसी कार्यालय

नई दिल्ली/मुंबई

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रभागों में उसके कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च, 2025 को खुले रहेंगे।

थाईलैंड-म्यांमार में भूकंप, इमारतें ढहीं

बैंकॉक (थाईलैंड)/(म्यांमार)

थाईलैंड और म्यांमार में दोपहर आए शक्तिशाली भूकंप से भारी अनिष्ट होने की आशंका है। एक बहुमंजिला इमारत समेत तमाम आवासीय भवन रेत के महल की तरह भरभरा गए हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 67 लोग लापता बताए गए हैं। भूकंप का असर भारत तक दिखा है। नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में लोगों ने कंपन महसूस किया। थाईलैंड में सेना को राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगटार्न शिनावात्रा अपनी फूकेत की यात्रा अधूरी छोड़कर बैंकॉक लौट रहे हैं। बैंकॉक के अखबार द नेशन की खबर के अनुसार, अधिकारियों का कहना है कि भूकंप के बाद देश में परिवहन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी में घटकर 2.9 फीसदी पर

नई दिल्ली

देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर फरवरी में घटकर पांच महीने के निचले स्तर 2.9 फीसदी पर आ गई है। पिछले साल इसी महीने में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 7.1 फीसदी रही थी।

जनवरी, 2025 में इसकी वृद्धि दर 4.1 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि देश के आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दर फरवरी महीने में घटकर पांच महीने के निचले स्तर 2.9 फीसदी पर आ गई है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 7.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इससे पहले इन क्षेत्रों की वृद्धि दर 2.4 फीसदी सितंबर में दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय के मुताबिक कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और बिजली क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि क्रमशः 1.7 फीसदी, 0.8 फीसदी, 5.6 फीसदी और 2.8 फीसदी रही है। जबकि पिछले वर्ष फरवरी में यह दर 11.6 फीसदी, 2.6 फीसदी, 9.4 फीसदी और 7.6 फीसदी रही थी। हालांकि, इस दौरान उर्वरक तथा सीमेंट क्षेत्र के उत्पादन में क्रमशः 10.2 फीसदी और 10.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-फरवरी अवधि के दौरान कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर 4.4 फीसदी रही। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में यह 7.8 फीसदी थी।

किसानों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित: शिवराज सिंह

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनका डेटा राज्यों के पास पूरी तरह से सुरक्षित है। किसानों का डेटा उनकी सहमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता। डिजिटल धोखाधड़ी और किसानों के डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल के "राग दरबारी" के एक किसान पात्र लंगड़ का जिक्र किया, जिसे अधिकारियों के तमाम चक्कर काटने के बाद भी खेत की नकल नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि उस पात्र के माध्यम से लेखक ने किसानों की समस्याओं को जिस तरह से दशार्या, उसे कांग्रेस सरकार नहीं समझ सकी लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समझा। उसी का नतीजा है कि डिजिटल कृषि मिशन बनाकर किसान की सारी दिक्कतें समाप्त करने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री को राज्य में राजस्व रिकार्ड से जोड़ा गया है, जिससे वह तत्काल अपडेट हो सके। ताकि जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी रहे। मंत्री ने बताया कि अगर किसी किसान ने अपनी जमीन किसी और को बेच दी तो तत्काल किसान रजिस्ट्री में अपडेट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, किसान रजिस्ट्री के दौरान कुछ समस्याएं आती हैं लेकिन उनके समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र कार्य करता है। इसमें किसान मोबाइल या वेब एप्लिकेशन का उपयोग कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति से सेवाओं में और योजनाओं का लाभ देने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। एक प्रधानमंत्री थे, जो कहते थे कि 1 रुपये भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचता है लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी बिहार के भागलपुर में एक बटन दबाते हैं तो 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है।

होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते

खाने का सर्विस चार्ज देना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में खाने का सर्विस चार्ज देना ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों पर सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने ये आदेश फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के 4 जुलाई 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस आदेश पर जुलाई 2022 में ही रोक लगा दिया था।

याचिका में कहा गया था कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सर्विस चार्ज पर रोक लगाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना। ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने का फायदा रेस्टोरेंट के स्टाफ को मिलता है। ऐसा करने से रेस्टोरेंट के मालिकों के व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होती है। इस दलील का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि याचिकाकताओं ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया कि सर्विस चार्ज से होटल और रेस्टोरेंट के स्टाफ को लाभ मिलता है। सुनवाई के दौरान सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि सर्विस चार्ज उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई से वसूली जाती है। याचिका में कहा गया था कि सर्विस चार्ज पिछले कई सालों से वसूला जा रहा है।

एटीएम से अतिरिक्त निकासी पर 01 मई से लगेगा ज्यादा शुल्क

नई दिल्ली/मुंबई

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों को एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ग्राहकों को अब एटीएम से निःशुल्क निकासी सीमा खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर प्रति लेन-देन 23 रुपये देने होंगे। पहले इसके लिए 21 रुपये देना पड़ता था। नए नियम 01 मई से लागू होंगे। आरबीआई की तरफ से जारी की गई जानकारी में बताया गया है कि बैंकों को 01 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर शुल्क दो रुपये बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेन-देन करने की अनुमति दे दी गई है। नए नियमों के अनुसार तय सीमा से ज्यादा बार पैसे निकालने की स्थिति में एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्क दो रुपये बढ़ाया गया है। पहले इसके लिए 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन देना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहकों को प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये देना होगा।

बैंकों में 31 मार्च को रहेगी चेक की क्लियरिंग व्यवस्था

आरबीआई ने सभी बैंकों से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी सरकारी लेन-देन के लेखांकन की सुविधा को लेकर 31 मार्च को विशेष क्लियरिंग व्यवस्था में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा है। मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत सामान्य समाशोधन का समय 31 मार्च, 2025 को वही होगा जो अन्य कामकाजी सोमवार को होता है।

किसान नेता जगजीत सिंहडल्लेवाल ने खत्म किया अनशन

नई दिल्ली

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन तोड़ दिया है। पंजाब सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाइवे को साफ कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया है। किसान नेता डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। संयुक्त किसान मोर्चा नेता डल्लेवाल ने किसानों की मांगों को लेकर 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खाली होने पर संतोष जताया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से दी गई इस जानकारी के मद्देनजर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया है।

लीक से हटकर करें काम, समाज के लिए बनेंगे प्रेरणास्त्रोत: मुख्यमंत्री

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधान भवन में युवाओं का एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को संबोधित किया। विधान सभा मंडप, विधान सभा सचिवालय में संपन्न कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए माई भारत अभियान के तहत युवाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य केवल यह नहीं कि आप नेता बनें, बल्कि आपके भीतर नेतृत्व का गुण पैदा हो, आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यापार, या किसी भी क्षेत्र में जाकर समाज की सेवा कर सकते हैं। जब आप लीक से हटकर कुछ नया और अतिरिक्त करते हैं, तो वह समाज के लिए प्रेरणा बनता है।

युवा संसद का उद्देश्य नेतृत्व का विकास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए युवा साथियों का इस मंच पर स्वागत है। यह आपके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 240 युवाओं का चयन किया गया है। जो आज देश की सबसे बड़ी विधायिका में चर्चा का हिस्सा बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौरवपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2019 से शुरू हुई युवा संसद की यह पहल जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व गुण विकसित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है।

संसदीय लोकतंत्र की ताकत

मुख्यमंत्री ने भारत के संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका एक-दूसरे के पूरक हैं। विधायिका नीति बनाती है तो कार्यपालिका उसे लागू करती है। न्यायपालिका नियमों की विवेचना करती है। ये तीनों मिलकर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन्होंने युवाओं को बताया कि विधानमंडल में जनप्रतिनिधि नियमों के तहत अपनी बात रखते हैं और यही प्रक्रिया देश की नीतियों और कानूनों को आकार देती है। अगर कहीं कोई शिकायत है तो जनता के पास कार्यपालिका और न्यायपालिका के मंच भी उपलब्ध हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र की ताकत है।

संविधान और कर्तव्य का महत्व

मुख्यमंत्री ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को इसका मसौदा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की। जिससे हम अपने संविधान निमार्ताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकें।

केंद्र सरकार ने ओला, उबर जैसी कंपनियों के प्रभाव को कम करने के लिए लॉन्च की 'सहकार टैक्सी' सेवा

एजेंसी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने गुरुवार को नई कॉपरेटिव टैक्सी सर्विस 'सहकार टैक्सी' को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बाइक, कैब और ऑटो सर्विस उपलब्ध कराना है। इस कॉपरेटिव टैक्सी सर्विस के लॉन्च से ऑनलाइन टैक्सी बाजार में प्रभुत्व रखने वाले ऐप जैसे ओला, उबर और रैपिडो को चुनौती मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य एक वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराना है, जहां चालक बड़ी कंपनियों के साथ लाभ साझा किए बिना सीधे कमाई कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में इस पहल की घोषणा करते हुए कहा, 'सहकार टैक्सी देश भर में दोपहिया टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और चार पहिया टैक्सियों का पंजीकरण करेगी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'सहकार से समृद्धि' सिर्फ एक नारा नहीं है, इसे साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पिछले साढ़े तीन साल में दिन-रात काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सहकार टैक्सी सेवा आने वाले महीनों में शुरू की जाएगी। निजी कंपनियों के विपरीत, यह सरकार समर्थित सेवा यह सुनिश्चित करेगी कि सारी कमाई ड्राइवरों के पास ही रहे, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा। केंद्रीय सहकारिता

मंत्री ने कहा, इस सेवा से होने वाला लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं मिलेगा, बल्कि वाहन चालकों को मिलेगा। शाह ने कहा कि इसके अलावा एक सहकारी बीमा कंपनी भी बनाई जाएगी जो देश में लोगों को बीमा सेवाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि छोटे समय में, यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। नई पहल का उद्देश्य ड्राइवरों को सशक्त बनाना है। साथ ही यात्रियों को विश्वसनीय और लागत प्रभावी परिवहन विकल्प प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल में यात्री साथी नाम से एक ऐसा ही सर्विस पहले से ही चल रही है, जो पहले सिर्फ कोलकाता में उपलब्ध थी। अब इसका विस्तार सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में भी हो गया है। यात्री साथी क्रिक बुकिंग, स्थानीय भाषा में जानकारी, किफायती किराया और चौबीसों घंटे कस्टमर सपोर्ट भी प्रदान करती है, जिससे यह यात्रियों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। 2022 में सरकारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा 'केरल सवारी' शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य था। हालांकि कम उपयोग के कारण इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार अब संशोधित किराए और बेहतर सॉफ्टवेयर के साथ इसे फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।

शाह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस खारिज

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। जयराम रमेश के इस नोटिस को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। जयराम रमेश का कहना था कि अमित शाह ने राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष, सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। जयराम रमेश ने 25 मार्च को %आपदा प्रबंधन विधेयक-2024% पर बहस के दौरान गृह मंत्री द्वारा दिए गए कथन का उल्लेख किया था। जयराम रमेश ने गृह मंत्री

के उस बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस शासन में बना और पीएम केयर मोदी सरकार में बना। कांग्रेस के शासन में एक ही परिवार का नियंत्रण होता था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य बनाए गए थे। इस विषय पर राज्यसभा के सभापति ने सदन में कहा कि 26 मार्च, 2025 को उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ 26 मई की तारीख दी है, जिसे संदर्भ में बदलाव नहीं होने के कारण अनदेखा किया जा सकता है। यह नोटिस जयराम रमेश ने राज्यसभा के नियम-188 के तहत गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहीं, राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष, सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। सभापति ने कहा कि यह मामला मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा में आया है। अगर अध्यक्ष के पास सूचना भेजी जाती है, जैसा कि बुलेटिन में संकेत दिया गया है और एक दीर्घकालिक परंपरा के तहत इसे प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित हनी-ट्रैप की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका खारिज की

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के विधायकों, राजनीतिक नेताओं और न्यायाधीशों के कथित हनी-ट्रैप की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग को लेकर प्रस्तुत जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने बिनय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष न्यायालय अथवा शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली समिति से जांच की निगरानी करने का आग्रह किया गया था। याचिका में कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया गया है, जिन्होंने 20 मार्च को दावा किया था कि राजनेताओं सहित

लगभग 47 हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को हनी-ट्रैप के प्रयासों का निशाना बनाया गया था।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी घटनाएं न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता कर सकती हैं और न्यायाधीशों को अनुचित प्रभाव में डाल सकती हैं, जिससे निष्पक्ष रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता कम हो सकती है। याचिका में कहा गया है, बाहरी प्रभाव से प्रभावित न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायी अतिक्रमण पर अंकुश नहीं लगा पाती। अगर न्यायाधीश ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, तो अदालतें तानाशाही, भ्रष्टाचार या कॉर्पोरेट लालच के खिलाफ़ सुरक्षा कवच के रूप में काम नहीं कर सकतीं। पीठ ने याचिका सीधे यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें कोई दम नहीं है।

सचदेवा ने की भारद्वाज के बयान की निंदा

नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान की आलोचना की है और कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री भारद्वाज गत वित्त वर्ष के बजट को आप सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि तत्कालीन आप सरकार अपने पूरे बजट को भी खर्च नहीं कर पायी थी। श्री सचदेवा ने मीडियाकर्मियों से कहा कि श्री भारद्वाज यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार खज़ाने में धन छोड़कर गई थी, जबकि सच्चाई यह है कि आप सरकार दिल्ली के विकास और रखरखाव में विफल रही तथा सरकारी खजाने को लूटा।

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति

एजेंसी

नयी दिल्ली। सरकार ने राजस्थान और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयों में सात स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तीन अपर न्यायाधीशों को उसी न्यायाल में एक वर्ष के लिए पुनः अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का निर्णय किया गया है।विधि एवं न्याय मंत्रालय की गरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायलय में चार अधिवक्ताऔर पंजाब उच्च न्यायालय के तीन अपर न्यायाधीश क्रमशः इन न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है,÷भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने' ये नियुक्तियां की हैं। सर्वश्री आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और

सत्यमेव जयते
विधि और न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

संदीप शाह (सभी अधिवक्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन अपर न्यायाधीशों सुमीत गोयल, श्रीमती सुदीप्ति शर्मा, तथा सुश्री कीर्ति सिंह को इस न्यायलय में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल में कार्यरत अपर न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत, राधाकिशन अग्रवाल और संजय कुमार जायसवाल को इसी न्यायालय में एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः इसी पद पर नियुक्त किया गया है।

पिता ने चार बच्चों की गला रेतकर हत्या की, बाद खुद को लगाई फांसी

शाहजहांपुर । उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने चार मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना थाना रोजा क्षेत्र के मानपुर चचरी गांव की है। बताया जा रहा है कि इसी गांव का रहने वाला राजीव अपने घर में था। उसकी तीन बेटियां और एक बेटा है। देर रात किसी समय राजीव ने अपनी बेटी स्मृति (13), कीर्ति (9) प्रगति (7) और बेटे ऋषभ (5) की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद राजीव ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। राजीव के पिता पृथ्वीराज घर के बाहर सो रहे थे। सुबह जब पृथ्वीराज ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। f

दिल्ली में अपराध रोकने में भाजपा विफल: दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी

नयी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में बढ़ते अपराध को रोकने में अक्षमता के कारण इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराना नहीं चाहती है। सुश्री आतिशी ने विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को आज लिखे पत्र में कहा है कि विधानसभा सत्र में नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख का समय तय हुआ है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाकों में बढ़ते हुए अपराध के मुद्दों को विशेष उल्लेख के लिए विधानसभा कार्यालय में आवेदन जमा किया था, लेकिन देर शाम मुझे विधानसभा सचिवालय से फोन आया और मुझे बताया गया कि अध्यक्ष ने पांच विधायकों के

विशेष उल्लेख खारिज कर दिए हैं, क्योंकि वे बढ़ते हुए अपराध के मुद्दों पर हैं और 'कानून व्यवस्था' दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।उन्होंने अध्यक्ष से कहा है कि यह बिल्कुल अचंभित करने वाला फैसला है। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है, तब से विधायकों ने अपने इलाके की समस्याएं विधानसभा पटल पर उठाई हैं। इस विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में कोई दुष्कर्म होगा, तो दिल्ली विधानसभा उस पर बात नहीं कर सकती, अगर दिल्ली की गलियों में गोलियां चलेंगी तो विधायक उस पर बात नहीं करेंगे, अगर महिलाओं के साथ हिंसा होगी तो विधानसभा उस पर मौन रहेगी। नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में बैठे 70 सदस्य अपने इलाके के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर यह अपने इलाके में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा नहीं उठायेंगे, तो कौन उठाएगा? ऐसा लगता है कि आप भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को रोकने में अक्षमता के कारण ये चर्चा रोकना चाहते हैं। चुनाव से पहले भाजपा कहती थी कि डबल इंजन की सरकार आने से दिल्ली की समस्याओं को हल करेंगे और चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि समस्याओं पर मुंह नहीं खोलने देंगे। चर्चा खत्म, तो समस्या खत्म! उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा है कि दिल्ली विधानसभा के पटल पर दिल्ली के हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान होगा।

कुणाल कामरा को विवादित टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने जारी किया दूसरा समन

मुंबई। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने विवादित टिप्पणी मामले में सुबह दूसरा समन जारी पूछताछ के लिए 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। कामरा के विरुद्ध उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरुद्ध विवादित टिप्पणी करने का मामला खार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को पेश होने को कहा था, लेकिन कामरा पुलिस स्टेशन में पेश नहीं हुए थे। उन्होंने वकील को खार पुलिस स्टेशन में भेजकर एक सप्ताह का समय मांगा था। जिसे पुलिस ने अस्वीकार कर दिया था और आज कामरा को दूसरा समन जारी कर 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है।

श्रीलंका की जेलों में बंद हैं 97 भारतीय मछुआरे: सरकार

एजेंसी

नई दिल्ली । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को बताया कि अभी 97 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेलों में बंद हैं। डा . जयशंकर ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों में इस संबंध में कड़े कानून बनाये हैं। भारत सरकार मछुआरों की रिहायी के बारे में श्रीलंका सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर समय समय पर बात करती रहती है। उन्होंने कहा कि गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाने वाले मछुआरों की सहायता के लिए सरकार उनकी नौकाओं पर ट्रांसपोंडर लगाने का काम कर रही है। इसके अलावा मछुआरों को दूसरे विकल्प भी दिये जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के

अंतर्गत भी मछुआरों को सहायता दी जाती है।पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि केरल में मानव- पशु संघर्ष की घटनाओं में 344 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि 344 लोगों में से ज्यादातर की सांप के काटने से मृत्यु हुई है जबकि एक सौ तीन लोगों की मृत्यु हाथियों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थिति के अध्ययन के लिए कोयम्बटूर में एक वैज्ञानिक केन्द्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव कानूनों के तहत पंचायतों को भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई जानवर फसलों या मनुष्यों के लिए खतरनाक हो जाता है तो उसे मारा जा सकता है।प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश में परमाणु कार्यक्रम के जनक डा. होमी जहांगीर भाभा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने न्यूक्लियर मिशन के गठन की घोषणा की है। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने तथा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल किया जायेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।

भाजपा घबराई, द्वी-भाषा नीति पर तमिलनाडु की आवाज निष्पक्ष परिसीमन सम्मान-न्याय की लड़ाई: स्टालिन

एजेंसी

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एम के स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि द्वी -भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर तमिलनाडु की दृढ़ और निष्पक्ष आवाज ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को परेशान कर दिया है। श्री स्टालिन ने इसे सम्मान और न्याय की लड़ाई करार करार देते हुए कहा कि द्रमुक कभी किसी भाषा का विरोध नहीं करती है, बल्कि किसी भाषा को थोपने और अंधराष्ट्रवाद का विरोध करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में श्री स्टालिन ने कहा कि यह राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर है। उन्होंने कहा, द्वी -भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन पर तमिलनाडु की निष्पक्ष और दृढ़ आवाज पूरे देश में गूंज रही है और भाजपा स्पष्ट रूप से घबरा गई है। बस उनके नेताओं के साक्षात्कार देखें। उन्होंने कहा, ÷अब योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर व्याख्यान देना चाहते हैं? हमें बख्श दें। यह विडंबना नहीं है - यह राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी का सबसे काला दौर है।÷उन्होंने कहा, हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते। हम इसी भाषा को थोपे जाने

और अंधराष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। यह वोट के लिए दंगा करने की राजनीति नहीं है। यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है।

डीआरडीओ, भारतीय नौसेना ने वीएलएसआरएसएएम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया

एजेंसी

नयी दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल-लॉन्च्ड शॉर्ट-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (वीएलएसआरएसएएम) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह उड़ान परीक्षण एक भूमि-आधारित वर्टिकल लॉन्चर से बहुत ही नजदीकी रेंज और कम ऊंचाई पर एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के खिलाफ किया गया। इस उड़ान ने मिसाइल प्रणाली की निकट-सीमा-कम ऊंचाई क्षमता को स्थापित किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने बहुत ही नजदीकी रेंज में लक्ष्यों को भेदने के लिए आवश्यक उच्च टर्न रेट को निष्पादित करके लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और मिसाइल की चपलता, विश्वसनीयता और सटीक सटीकता को स्थापित किया। बयान में

कहा गया है कि यह परीक्षण सभी हथियार प्रणाली तत्वों को लड़ाकू विन्यास में तैनात करके किया गया था। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, मल्टी-फंक्शन रडार और हथियार नियंत्रण प्रणाली वाली मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहा।आईटीआर चांदीपुर द्वारा विकसित विभिन्न रेंज उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा द्वारा सिस्टम के प्रदर्शन को मान्य किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योग को बधाई देते हुएमिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास में भारत की मजबूत डिजाइन और विकास क्षमताओं का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय नौसेना के लिए एक उत्कृष्ट बल गुणक होगा। इस बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने भी डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित टीमों को इस सफल उड़ान परीक्षण पर बधाई दी और कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस यह मिसाइल सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी बढ़ावा देगी।

सज-धज कर तैयार हुआ 14 किलोमीटर का उत्तरवाहिनी नर्मदा का परिक्रमा मार्ग

एजेंसी

राजपीपला। गुजरात में वडोदरा और नर्मदा से होकर गुजरने वाली नर्मदा नदी जिले में लगभग 6 किलोमीटर तक उत्तर दिशा में बहती है, इसीलिए प्रति वर्ष चैत्र महीने में उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा आयोजित की जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस वर्ष 29 मार्च से उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा शुरू होने जा रही है, जो आगामी 27 अप्रैल यानी लगभग एक महीने तक चलेगी। इस परिक्रमा में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में भक्तों के उमड़ने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इस 14 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग पर 3.82 करोड़ रुपए के खर्च से विभिन्न सुविधाएं विकसित कर यात्रियों की व्यवस्था की है। नर्मदा परिक्रमार्थियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बोर्ड द्वारा अनेक अस्थायी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। उत्तरवाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में नर्मदा नदी के शहेराव घाट, रेंगण घाट, रामपुरा घाट और तिलकवाड़ा घाट स्थित हैं। बोर्ड द्वारा इन सभी घाटों पर बड़े आकार के मंडप, कुर्सियां, बैरिकेडिंग, लाइटिंग, टॉयलेट ब्लॉक, चेन्जिंग रूम, मेडिकल बूथ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पुलिस बूथ के लिए मंडप, पेयजल सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, चेतावनी बोर्ड, डीजी सेट, साइन बोर्ड, पार्किंग, यात्रियों को लाइन में खड़े रहने के लिए रेलिंग, वॉच टावर, फूड स्टॉल और स्नान आदि की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, पूरे परिक्रमा मार्ग पर लाइटिंग, साइनेज, डस्टबिन, सीसीटीवी कैमरे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था, टॉयलेट यूनिट, आपातकालीन स्थिति के लिए जेसीबी, हिताची, क्रेन और रस्सों जैसी मशीनरी आदि की व्यवस्था की गई है।

अखिलेश पर हावी हो चुकी मुगलिया सोच, कर रहे सनातन का अपमान: भाजपा

एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश यादव के गौशाला व दुर्गंध के बयान पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। अखिलेश के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता, संघ कार्यकर्ता एवं गौभक्तों में खासी नाराजगी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव पर मुगलिया सोच हावी हो चुकी है। वह लगातार भारतीय सनातन संस्कृति और मूल्यों का अपमान करते जा रहे हैं। जिन्होंने गौशाला में कदम तक नहीं रखा, वह सुगंध और दुर्गंध की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि इत्र पार्क बनाने के साथ-साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो। गौशाला में सनातन की आस्था को तलाश करो। ये गौमाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गौ ?सेवा में लखनऊ विभाग के संयोजक शरद ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपनी पहले की पीढ़ियों से शिक्षा लेनी चाहिए। जिन्होंने गाय माता की जीवनभर सेवा की है। गाय माता के दूध दही का व्यापार किया है। आज भी यदुवंश बड़ी संख्या में दूध दही का व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाय माता के घर को हम गौशाला के रूप में जानते हैं। गौशाला में गोबर से दुर्गंध की बात करने वाले यह नहीं जानते है कि आज भी लोगों के घरों में यज्ञ हवन करने से पहले जमीन को गोबर से स्वच्छ करते है।

नाबालिक दोस्तों ने नौवीं क्लास के छात्र का गला रेतकर किया कत्ल, फिर मांगे 10 लाख रुपए

नई दिल्ली।
राजधानी दिल्ली के वजीराबाद में नाबालिग दोस्तों ने नौवीं के छात्र का पहले किया अपहरण फिर कर दी हत्या। उसके बाद परिजनों से दस लाख रुपये फिरौती की मांग कर दी। हालांकि, पुलिस ने को छात्र का शव बरामद कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, (15 वर्षीय) वैभव परिवार सहित मिलन विहार इलाके में रहता था।

वैभव के पिता विकास गर्ग पेशे से ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुखर्जी नगर स्थित स्कूल में कक्षा नौवीं का छात्र था। वैभव रविवार को घर से खेलने के लिए गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। इस बारे में पुलिस को सोमवार को सूचना दी गई। परिजन

के मोबाइल पर वैभव के मोबाइल नंबर से एक फोन आया। फोन करने वाले ने वैभव की जान बचाने के लिए दस लाख रुपये की मांग रखी। वैभव के परिजनों ने पुलिस को कॉल के बारे में जानकारी दी। जांच के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तीन नाबालिगों को पकड़ा जब पुलिस ने संदिग्ध मान कर पूछताछ की,तो उन्होंने हत्या की बात कबूल की। हैरानी की बात यह है कि तीनों आरोपी वैभव के घर के पास रहते थे।

तीनों रविवार को योजना के तहत वैभव को बहला फुसला कर अपने साथ भलस्वा डेरी झील के पास जंगल में ले गए। जहां पर इन्होंने वैभव का गला काट दिया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।

स्वरूप नगर में बेरहमी से ईट मारकर कर दी हत्या, बोरवेल के गड्ढे में फेंकी लाश

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर में एक शख्स की हत्या के बाद उसकी लाश बोरवेल में फेंकने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान (24 वर्षीय) सूरज (20 वर्षीय) अंकित और (22 वर्षीय) अभिषेक के रूप में हुई है, ये सभी स्वरूप नगर के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो सूरज और अभिषेक पहले भी तीन-तीन आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। मृतक की पहचान चंदन के रूप में हुई है

दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों ने पहले शख्स की ईंटों से पीट-पीट कर हत्या कर दी और बाद में उसकी लाश को बोरवेल के गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) निधिन वाल्सन ने कहा कि सूरज को हाल ही में शस्त्र अधिनियम के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को संदेह था कि चंदन उसकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार था और उसने अन्य दो आरोपियों के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। यह घटना 22 मार्च को हुई जब सूरज ने चंदन को शराब पीने के बहाने बुलाया। अत्यधिक शराब पीने के बाद,आरोपियों ने ईंटों से उस पर हमला किया और मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने उसके शव को एक निमार्णाधीन पंप हाउस में बोरवेल के गड्ढे में फेंक दिया, और उसे ईंटों से ढक दिया।

डीसीपी ने कहा कि 23 मार्च को, चंदन के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया जब वह घर नहीं लौटा तो स्वरूप नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान,सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चंदन को आखिरी बार सूरज के साथ देखा गया था। इस सुराग के आधार पर,सूरज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार पूछताछ के बाद,उसने अपराध कबूल कर लिया और मामले में अंकित और अभिषेक की संलिप्तता का खुलासा किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद,वे पुलिस टीम को अपराध स्थल पर ले गए,जहां चंदन का शव बरामद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि हत्या में इस्तेमाल की गई ईंटें भी मौके से बरामद की गईं। अधिकारी ने आगे कहा कि पीड़ित के शव को ले जाने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी,उसके मोबाइल फोन के साथ बरामद की गई। डीसीपी ने बताया कि आगे की जांच चल रही है।

भारत में 284 अरबपति, कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपये?

नई दिल्ली । भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 284 हो गई है, जिनकी कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपये है। को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट फॉर 2025 से पता चलता है कि देश के सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति में पिछले एक साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अकेले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 90 अरबपति हैं। भारत वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में बना हुआ है, अरबपतियों की संख्या के मामले में देश तीसरे स्थान पर है, जो केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। अमेरिका 870 अरबपतियों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है।

हुरुन रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 175 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि हुई है, जबकि 109 की संपत्ति में या तो गिरावट आई है या कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एक भारतीय अरबपति की औसत संपत्ति अब 34,514 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, भारत में 40 वर्ष से कम आयु के सात अरबपति हैं, जिनमें से अधिकांश बेंगलुरु और मुंबई के हैं।

ग्लोबल फ्रंट पर टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने पिछले साल 189 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ सबसे बड़ी संपत्ति वृद्धि दर्ज करवाई। अरबपति ने पांच साल में चौथी बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा और वह 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए।

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 266 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इस बीच, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के एआई और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड में मजबूत निवेशक विश्वास के कारण पहली बार टॉप तीन में जगह बनाई।

इस साल की हुरुन लिस्ट में मनोरंजन, खेल और सोशल मीडिया से भी नाम शामिल रहे। इनमें सिंगर जे-जेड, रिहाना, टेलर स्विफ्ट और पॉल मेकार्टनी शामिल रहे।

अरबपति क्लब में जगह बनाने वाली खेल हस्तियों में माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स, फ्लॉयड मेवेदर, लेब्रोन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी शामिल रहे। किम कार्दशियन वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र प्रभावशाली हस्ती रहीं।

अमित शाह का बड़ा आरोप: टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड जारी करती है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड जारी कर रही है।

लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के रास्ते भारत में आते थे। अब टीएमसी सरकार के कारण वे पश्चिम बंगाल के रास्ते आ रहे हैं।" गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि

"जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए, उनके पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के आधार कार्ड मिले हैं।" उन्होंने सवाल उठाया कि इन्हें आधार कार्ड जारी करने का जिम्मेदार कौन है और यह घुसपैठिए दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं।

टीएमसी पर हमला तेज

अमित शाह ने सीधे तौर पर टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "आप (टीएमसी) आधार कार्ड जारी करते हैं, तभी ये लोग वोटर कार्ड बनवा पाते हैं और देश में घुसपैठ बढ़ती है। अगर आप इन्हें दस्तावेज जारी न करें, तो ये भारत में पैर भी नहीं रख सकते।"

यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरम है और आगामी चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी की ओर से इस आरोप पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

गोला-बारूद और मिसाइल क्षमता से लैस भारतीय नौसेना का 10वां बार्ज (शिप) लॉन्च

नई दिल्ली । गोला-बारूद और मिसाइल की क्षमता से लैस भारतीय नौसेना के एक और अत्याधुनिक बार्ज (शिप) को लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही ऐसी कुल 9 आधुनिक बार्ज पहले ही भारतीय नौसेना को मिल चुकी हैं।

गौरतलब है कि बार्ज एक प्रकार का छोटा जहाज है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से नौसेना के अत्याधुनिक हथियारों व उपकरणों को लाने ले जाने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में किया जाता है। बार्ज सामान्यतः समुद्र या महासागर में बहुत आगे तक नहीं जाते हैं। लेकिन वे यहां तैनात बड़े नौसैनिक जहाजों के साथ संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा नदियों, नहरों और अंतर्देशीय जलमार्गों में माल परिवहन के लिए भी इनका व्यापक उपयोग हो रहा है। यह भारतीय नौसेना की 10वें गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल (एसीटीसीएम), एलएसएएम 24 (यार्ड 134) बार्ज है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसे लॉन्च करने का समारोह मैसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे में किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि कमोडोर राहुल जगत, एसपीएस, पनडुब्बी निगरानी दल (एसओटी) मुंबई थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एमएसएमई शिपयार्ड, मैसर्स सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, के साथ 11 गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बार्ज के निर्माण का अनुबंध 5 मार्च, 21 को हुआ था। इन नौसैनिक बार्जों को भारतीय पोत डिजाइन फर्म और भारतीय शिपिंग रजिस्टर (आईआरएस) के सहयोग से निर्मित किया गया है। यानी ये भारत में ही बने और भारत में ही डिजाइन किए गए स्वदेशी रूप से बने बार्ज हैं।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक समुद्री कौशल सुनिश्चित करने के लिए नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल), विशाखापत्तनम में इस बार्ज का मॉडल परीक्षण किया गया था। शिपयार्ड ने अभी तक 11 बार्ज में से नौ की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की थी। भारतीय नौसेना द्वारा अपने परिचालन विकास के लिए प्रभावी रूप से इनका उपयोग किया जा रहा है। ये बार्ज भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना की शक्ति में बीते कुछ महीनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जहां एक ओर भारतीय नौसेना को बड़े समुद्री युद्धपोत मिले हैं, वहीं दूसरी ओर कई आधुनिक बार्ज भी नौसेना का हिस्सा बने हैं।

औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारक की सूची से हटाने की मांग, गजेंद्र सिंह शेखावत को राहुल शेवाले ने लिखा पत्र

मुंबई,। औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची से हटाने की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस संबंध में मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा। उनका कहना है कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत संरक्षित है। ऐसे में इस कब्र सरकारी संरक्षण प्राप्त है, जबकि कई वर्षों से इस कब्र को उखाड़ने की मांग की जा रही है।

राहुल शेवाले ने पत्र में औरंगजेब की कब्र को संरक्षित स्मारक से हटाने की मांग को सशक्त रूप से उठाया है। उनका कहना है कि औरंगजेब का इतिहास अत्याचार और धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक बन चुका है, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, जहां उसकी क्रूरता और सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के साथ किए गए अत्याचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की गई और इससे पहले धर्म परिवर्तन न करने पर उन्हें 40 दिनों तक नृशंस यातनाएं दी गईं। ये घटनाएं औरंगजेब के शासन के क्रूर पक्ष को उजागर करती हैं।

शिवसेना नेता ने कहा कि हालांकि यह स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन आता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि औरंगजेब की कब्र को कब और कैसे संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में यह स्थल प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित है

मुस्लिम के गरीब परिवार को मोदी सरकार देगी सौगात ए उपहार

नई दिल्ली। ईद से पहले देश भर में भारतीय जनता पार्टी देगी 32 लाख वंचित मुसलमानों को विशेष किट वितरित करने के उद्देश्य से अपना सौगात-ए-मोदी अभियान शुरू करने जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होने जा रही इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब मुस्लिम परिवार बिना किसी कठिनाई के त्योहार मना सकें।

अभियान के तहत, 32,000 अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए देश भर की 32,000 मस्जिदों के साथ सहयोग करेंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि रमजान के पवित्र महीने और ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज और भारतीय नववर्ष जैसे आगामी अवसरों पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात-ए-मोदी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। सौगात-ए-मोदी ईद किट पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी का विकास एजेंडा कभी भी वोटों के लिए नहीं रहा है। पिछले ग्यारह सालों में उन्होंने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। विकास के मामले में उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहां तक ??कि जो लोग मोदी को वोट देने से कतराते हैं, वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं।सौगात-ए-मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इस किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे इत्यादि खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे।

अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ : ट्रंप प्रभाव को कम करने के लिए भारत के पास जीत का रास्ता मौजूद

नई दिल्ली। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ दो अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में को आई रिपोर्ट के अनुसार, आगामी टैरिफ को देखते हुए भारत द्वारा अमेरिका को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में रियायतें देकर बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही भारत को यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि देश के घरेलू उद्योग को इससे कोई नुकसान न पहुंचे।

ट्रंप के "लव फोर अ डील" के बीच तेजी से बदलते वैश्विक व्यापार गतिशीलता में, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भारत के लिए कुछ "आसान जीत" की पहचान की है।

इनमें अमेरिका से ऊर्जा (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस) आयात बढ़ाना, रक्षा खरीद और सहयोग को बढ़ाना, कुछ कृषि/खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम करना और विदेशी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर शुल्क कम करना शामिल है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा कि वैल्यू चेन में सेक्टर या कमोडिटी लेवल के टैरिफ आकलन के आसपास की जटिलताओं को देखते हुए, दो

अप्रैल को ब्रांड सेक्टर लेवल रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की सबसे ज्यादा संभावना है।

उन्होंने कहा, "ग्लोबल ट्रेड वॉर के इस नए चरण में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अंत में, हमारा विचार है कि टैरिफ भारत के लिए एक बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि वार्ता फलदायी होगी, जिसका अमेरिका के लिए ओवरऑल भारतीय निर्यात पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा।"

मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ के लिए, कुछ निर्यात अवसर रिफाइंड पेट्रोलियम, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिकी सप्लाई चेन के इंटीग्रेटेड नेचर का मतलब है कि कोई भी लाभ अगर संभव हुआ तो भारत को इसे मिलने में समय लगेगा।

ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत टैरिफ को काफी कम कर देगा, लेकिन रेसिप्रोकल रेट वसूलने की उनकी योजना के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा, "मुझे लगता है कि वे संभवतः उन टैरिफ को काफी हद तक कम करने जा रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल को हम उनसे वही टैरिफ वसूलेंगे, जो वे हमसे वसूलते हैं।"

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस महीने वाशिंगटन का दौरा किया और टैरिफ बढ़ोतरी को रोकने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से बात की।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी वापस ली गई

नई दिल्ली। अपने आवास से कैश मिलने के बाद विवादों में आये दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से अब प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले ली थीं। जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटियों के सदस्य थे। हाई कोर्ट ने नये सिरे से प्रशासनिक कमेटियों का गठन किया है जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा नहीं हैं। जस्टिस वर्मा पहले 14 कमेटियों के सदस्य थे। जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पूरी न्यायपालिका और राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश दिया था। कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की अनुशंसा की है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25 में राष्ट्रीय राजमार्गों की रखरखाव के लिए मंजूर किए 9,599 करोड़ रुपये

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 25 में राष्ट्रीय राजमार्गों की रखरखाव के लिए 9,599 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने को दी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसमें 2,842 करोड़ रुपये के मूल्य के 17,884 किलोमीटर की लंबाई के शॉर्ट-टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एसटीएमसी) और 6,757 करोड़ रुपये के मूल्य के 6,118 किलोमीटर की लंबाई के परफॉरमेंस-बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (पीबीएमसी) शामिल हैं।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और एक जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया है।

वर्तमान में देश में 8.11 लाख करोड़ रुपये की लागत से 31,187 किलोमीटर लंबाई में 1,310 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निमार्णाधीन हैं।

वहीं, एसटीएमसी कार्य में अनुबंध सामान्यतः 1-2 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य में अनुबंध लगभग 5-7 वर्ष की अवधि के लिए किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने और रखरखाव की आवश्यकताओं को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी या तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कार्य शुरू होने से पहले, कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पहले और कार्य समाप्ति के बाद छह माह के नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों का नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) के माध्यम से आकलन किया जाता है, जिससे नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता आकलन संभव हो पाता है। इसके अलावा, सरकार ने चार लेन और उससे अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लगाने का काम शुरू कर दिया है।

गडकरी ने कहा, "एटीएमएस में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रावधान है, जो राजमार्गों पर घटनाओं (यातायात उल्लंघन राजमार्गों की निगरानी करने में मदद करते हैं।

संपादक की कलम से

कैसे रुक पायेगा राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण

हमारे देश के राजनेताओं में दिन-प्रतिदिन नैतिकता कम होती जा रही है। कई बड़े नेता आए दिन विवादास्पद बयान देखकर चचाओं में बने रहते हैं। वहीं बहुत से निर्वाचित विधायकों, सांसदों, मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर अपराधिक मामले दर्ज हो रहें हैं। जिससे राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों की छवि खराब होती जा रही है। देश की राजनीति में आज अपराध का इतना घालमेल हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा जनप्रतिनिधि अपराधी है और किसकी छवि स्वच्छ है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के नेता बनने से जहां राजनीतिक दागदार हुई है। वहीं नेताओं की जनता की दूरी भी बढ़ने लगी है। मौजूदा समय में राजनीतिक व्यवसाय बन चुकी है। राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जो या तो बड़े नेताओं के परिवार से है या फिर बहुत पैसे वाले हैं। राजनीति के क्षेत्र में अब सेवा, संगठन, वफादार कार्यकताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। राजनीति पूरी तरह पैसों की चकाचौंध में लिप्त हो गई है।

एक समय था जब धरातल पर काम करने वाला पार्टी कार्यकर्ता आगे चलकर जनप्रतिनिधि बनता था। जमीन से उठकर आगे आने वाला नेता आम जनता से जुड़ा रहता था और वह जनता के सुख-दुख से वाकिफ भी होता था। इसलिए वह आमजन के हित में काम करता था। मगर अब लोग पैसे के बल पर पैराशूट से उतरकर राजनीति करने लगे हैं। वह पैसे के बल पर ही चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए उन्हें आमजन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं रहता है। ऐसे नेता पांच सितारा संस्कृति के वाहक होते हैं। ऐसे नेता राजनीति में आने के लिए पहले खूब पैसा खर्च करते हैं और जब किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो जमकर भ्रष्टाचार कर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही आज राजनीति समाज सेवा की बजाय व्यवसाय बन गई है।

1971 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू सीट पर देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के कृष्ण कुमार बिड़ला को हराने वाले शिवनाथ सिंह गिल को मैंने 1998 से 2003 में विधायक के रूप में देखा है। वह अपने क्षेत्र से जयपुर जाते या अपने घर से विधानसभा जाते हमेशा सरकारी बस का ही उपयोग करते थे। कभी निजी गाड़ियों से नहीं घूमते थे। इसी के चलते उन्होंने राजनीति में 50 साल लंबी पारी खेली थी। वह ईमानदार थे इसीलिए ईमानदारी से रहते थे। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी कई लाख रूपयों की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। पार्टी का कोई नेता उनसे यह नहीं पूछता है कि इतनी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे कहां से आता है। सबको पता है की राजनीति में आज छूट-भैया नेता भी सत्ता की दलाली में पैसा कमा रहे हैं। दलाली के पैसों में बड़े नेताओं का भी हिस्सा होता है। इसीलिए उनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठाता हैं।

चुनाव सुधार पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के 45 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संगठन ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण किया है। जिसमें आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 यानी 79 प्रतिशत विधायकों ने जबकि सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक 3 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115 यानि 86 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उक्त रिपोर्ट से पता चला कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं। वहीं 226 पर धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 और 376 (2)(द) के तहत बलात्कार का आरोप है। धारा 376 (2)(द) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 (46 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से 27 को दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कुल 233 सांसदों (43 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। जबकि 2014 में 185 (34 प्रतिशत), 2009 में 162 (30 प्रतिशत) और 2004 में 125 (23 प्रतिशत) सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2024 में लोकसभा के लिये चुने गये 251 उम्मीदवारों में से 170 (31 प्रतिशत) पर बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला कि यह 2019 में 159 (29 प्रतिशत) सांसदों, 2014 में 112 (21 प्रतिशत) सांसदों और 2009 में 76 (14 प्रतिशत) सांसदों की तुलना में भी वृद्धि है।

एडीआर के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 (39 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 (49 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों में से 21 (45 प्रतिशत) पर आपराधिक आरोप हैं। विश्लेषण में पाया गया कि 63 (26 प्रतिशत) बीजेपी उम्मीदवार, 32 (32 प्रतिशत) कांग्रेस उम्मीदवार और 17 (46 प्रतिशत) समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसमें कहा गया है कि सात (24 प्रतिशत) टीएमसी उम्मीदवार, छह (27 प्रतिशत) डीएमके उम्मीदवार, पांच (31 प्रतिशत) टीडीपी उम्मीदवार और चार (57 प्रतिशत) शिवसेना उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

संविधान के नाम पर कांग्रेस का दोहरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण

-ललित गर्ग-

कांग्रेस एक बार फिर संविधान को लेकर विवादों से घिर गयी है। संविधान के संबंध में कांग्रेस का दोहरा रवैया एवं चरित्र एक बार फिर देश के सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर हाथ में संविधान की प्रति लेकर भाजपा पर इसे बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अपनी हर सभा में इस आरोप को दोहराते रहे कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, इसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद संविधान बदलने की बात कर रही हैं। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ओबीसी कोटा के तहत पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में जब उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को यह याद दिलाया गया कि संविधान के तहत मजहब के आधार पर आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने इशारा किया कि आरक्षण देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फिर संविधान बचाने का सियासी अभियान हावी हो गया है। इस बार भाजपा आक्रामक है और उसने फिलहाल इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह अहम मुद्दा बन जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये कांग्रेस सरकारें अपने-अपने राज्यों में अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं योजनाएं लागू करती रही हैं, कर्नाटक में भी वहां के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने सरकार का बजट पेश करते हुए मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने एलान किया कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-प्प बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इसका निर्माण वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर पैसा खर्च करेगी। मौलवियों को 6000 मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समुचित बजट आवंटित नहीं हुआ लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते मुस्लिमों के लिये लुभावना बजट आवंटित किया गया है। जबकि सरकारों का काम किसी धर्म एवं समुदाय विशेष का तुष्टिकरण न होकर सभी समुदायों का पुष्टीकरण होना चाहिए। जब संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का निषेध किया गया है तो फिर जानबूझकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे सूचीबद्ध करके विधि सम्मत क्यों बनाया जा रहा है?

दरअसल, भाजपा और कांग्रेस, दोनों देश की प्रमुख पार्टियों को यह एहसास हो चला है कि संविधान इस देश में बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर लोग कतई समझौता नहीं करेंगे। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है। संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए आघात करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्षी दल एवं कांग्रेस अत्यंत निकृष्ट राजनीति करती जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं। कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। संविधान को आधार बनाकर विपक्षी दल जनता को विभाजित करने, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने बाज नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य नहीं, कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो हथियार चलाया था, वही हथियार कर्नाटक में स्वयं कांग्रेस के विरुद्ध चला गया है। अब इससे होने वाले नुकसान का भान होते ही कांग्रेस तत्काल बचाव में लग गई। वैसे, शिवकुमार के स्पष्टीकरण के बावजूद भाजपा इस मुद्दे पर निशाना साध रही है, तो संकेत साफ है, वह सियासत का मौका जाने नहीं देना चाहेगी। वह संविधान बदलने और न बदलने पर फिर से गर्म हुई राजनीति को ठंडा नहीं होने देगी। बीते लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा निशाने पर थी, वहीं इस बार कांग्रेस निशाने पर आ गई है। लोकसभा-राज्यसभा में एवं इस वर्ष बिहार में होने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक रहेगी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, भले ही अब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार सफाई देने में लगे हैं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और वह संविधान में बदलाव का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे। स्पष्ट है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं है। डॉ. भीमराव आंबेडकर भी ऐसे आरक्षण के हिमायती नहीं थे। संविधान सभा में एकमत के साथ यह तय हुआ था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब अगर ऐसे आरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है, या कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिये आरक्षण का हथियार चलाती है तो संविधान में संशोधन तो करना ही होगा। अपने आजाद देश में जरूरतमंदों को आरक्षण देने के लिए करीब 12 बार संविधान में संशोधन किए गए है और मुस्लिमों को महज मजहबी बुनियाद पर आरक्षण देने के लिए भी ऐसी जरूरत पड़ेगी।

गांधी परिवार के अत्यंत करीबी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान को सुनकर लोग हैरत में हैं। लोग संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ा दी है।ह्व कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये देश को दांव पर लगाती रही है। एक बार फिर उसकी इस कोशिश से उसका असली चेहरा देश के सामने आया है। कांग्रेस भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, मुस्लिम आरक्षण को संविधान में जगह देकर संविधान निमार्ता बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफत की जा रही है। मुस्लिमों को आरक्षण असंवैधानिक हैं। कांग्रेस बार-बार मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर संविधान की मूल भावना को चुनौती दे रही है। मुस्लिम वोटबैंक के लिए ऐसा किया जाना संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ है। राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी का रवैया आरक्षण को लेकर समय-समय पर बदलता रहा है। कभी उसने संविधान संशोधन की बात की, तो कभी आरक्षण का विरोध किया, तो कभी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के प्रयास भी किए। आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस द्वारा ऐसा भी किया गया, जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना ही बदल डाली। कांग्रेस नेता संविधान की किताब जेब में रखते हैं, लेकिन इसे कमजोर करने के लिए हरसंभव कोशिश भी करते हैं। अब कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव क्यों करना चाहती है? कांग्रेस का रवैया हर प्रकार से संविधान विरोधी ही रहा है। संविधान को कमजोर करने वाले अनेक प्रयास कांग्रेस समय-समय पर करती आई है। कांग्रेस द्वारा अपने शासनकाल में इस पर संशोधन लाने का प्रयास किया गया कि सरकार संविधान में क्या-क्या परिवर्तन कर सकती है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हमारा संविधान केवल सत्ता को साधने का एक उपकरण मात्र रहा है, संविधान के प्रति सम्मान की भावना कांग्रेस के चरित्र में नहीं है। जबकि वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार संविधान के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की मंशा से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रेषक

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन,

एक कॉमेडियन से सरकार का डरना अपने आप में कॉमेडी है

- डॉ. दीपक पाचपोर

यह विधिसम्मत है। अब यह भी सोचें कि जो भाजपा, शिंदे की शिवसेना तथा अजित पवार कह रहे हैं या कर रहे हैं वह संविधानसम्मत या कानून के अंतर्गत है? बिलकुल नहीं! आयोजनस्थल की तोड़-फोड़ करना कानूनी तौर पर सही नहीं है क्योंकि मामले की अभी तक पुलिस जांच भी प्रारम्भ नहीं हुई है। यदि न्यायालय कुणाल कामरा की कॉमेडी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाता और कॉमेडियन को क्लीन चिट देता है तो क्या सरकार या महानगरपालिका उस होटल व स्टूडियो को मुआवजा देगी?

ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय...
ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय...
एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए...
मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए।
ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय।
मंत्री नहीं वो दलबदलू है और कहा क्या जाए...
जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए...
मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए...
तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे...
ठाणे की रिक्शा...ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय...।

मनोरंजन करके गुजारा करने वाले एक अदने से स्टैंडअप कॉमेडियन ने मुम्बई में एक शो के दौरान प्रसिद्ध हिन्दी मूवी 'दिल तो पागल है' के एक गीत की केवल 10 पंक्तियों की पैरोडी क्या सुना दी, महाराष्ट्र सरकार मानों सुलग उठी है। इस सरकार को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बौखलाई हुई हैं। पुलिस एफआईआर दज कर कामरा के खिलाफ एक्शन ले रही है, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बयान दिया है कि 'स्टैंडअप कॉमेडी की आजादी है लेकिन कोई भी जो चाहे वह नहीं बोल सकता।' उनके अनुसार 'कुणाल को माफी मांगनी चाहिये।' इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक उप मुख्यमंत्री अजित पवार कहते हैं कि 'किसी को भी कानून व संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिये', तो दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन पर यह पैरोडी रची गयी है, का कहना है- 'किसी पर हास्य-व्यंग्य करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी एक मयार्दा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वर्ना 'एक्शन का रिएक्शन' भी होता है।' पहले तो शिंदे को पता करना चाहिये कि सुपारी किसने दी है। खैर...

बहरहाल, रिएक्शन होता दिख रहा है। शो का आयोजन खार के जिस यूनिकांटिनेंटल क्लब में हुआ था उस आयोजन स्थल पर शिंदे गुट के कार्यकताओं ने तोड़-फोड़ कर दी, मुम्बई महानगरपालिका ने वहां हथौड़ा चला दिया, कार्यकर्ता पहले ही धमकी दे चुके हैं कि वे महाराष्ट्र तो क्या देश भर में कामरा को घूमने-फिरने तथा शो नहीं करने देंगे। पार्टी प्रवक्ता साफ कर चुके हैं कि 'कॉमेडियन से शिवसेना स्टाइल में निपटा जायेगा।' इतना ही नहीं, कामरा के साथ कुछ कार्यकर्ता फोन पर गाली-गलौज कर रहे हैं। मार्के की बात यह है कि मयार्दा व कानून में रहकर कॉमेडी करने की सलाह सरकार के तीनों ही धड़े निहायत ही अमर्यादित ढंग से और कानून को हाथ में लेकर दे रहे हैं। यही अपने आप में कॉमेडी है जो ऐसी ही सरकार कर सकती है जिसका बनना और चलना साक्षात कॉमेडी सर्कस है।

जामुन के अनगिनत फायदे

नई दिल्ली। गर्मी का सीजन शुरू होते ही कई ऐसे फल बाजार में आ जाते हैं, जिन्हें खाने के फायदे अनगिनत होते और शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। इन्हीं में से एक है जामुन। जो दिखने में तो एक छोटा सा फल है, लेकिन ये स्वाद में जितना अनोखा है, उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी है। बैंगनी रंग और तीखे-मीठे स्वाद के पीछे छुपे कई ऐसे गुण हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो चलिए, जानते हैं जामुन के उन फायदों के बारे में जो इसे प्रकृति का अनमोल तोहफा बनाते हैं।

दरअसल, जामुन का वैज्ञानिक नाम सिजीगियम क्यूमिनी है। जामुन भारत सहित दक्षिण एशिया में खूब पाया जाता है। गर्मियों में पैदा होने वाला जामुन स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। आमतौर पर इसको नमक के साथ खाया जाता है। बताया जाता है कि जामुन का फल 70 प्रतिशत खाने योग्य होता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा, ये अन्य फलों की तुलना में कम कैलोरी प्रदान करता है।

इतना ही नहीं, इस फल के बीज में काबोर्हाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी काफी अधिक होती है और इसमें विटामिन बी, कैरोटिन, मैग्नीशियम और फाइबर भी पाया जाता है।

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी ह्यजामुनह्ल के गुणों का लोहा माना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित (अक्टूबर, 2022) एक रिपोर्ट के अनुसार, जामुन को डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी चयापचय (मेटाबॉलिक) समस्याओं के इलाज में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से जामुन मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की स्थिति में भी फायदेमंद हो सकता है।

शोध के मुताबिक, नतीजों से पता चला कि जामुन इन समस्याओं के लक्षणों और संकेतकों को बेहतर करने में मदद करता है। कई शोधों में ये भी देखा गया कि जामुन न सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम बल्कि दूसरी बीमारियों में भी असरदार है। आज इसे लोक दवा के तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियों के खिलाफ आवाज

सोमवार को इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठनों ने शिक्षा के निजीकरण, भगवाकरण के विरोध और छात्र संघ की बहाली को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि सरकार आरएसएस की विचारधारा थोप रही है और शिक्षा को व्यापार बना रही है। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई, आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, सीआरजेडी और समाजवादी छात्रसभा ये सभी छात्र संगठन एक बैनर के तले पहुंचे। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार की नीतियों से शिक्षा महंगी हुई है. गरीब बच्चों की पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर होती जा रही है। छात्रों ने आरोप है कि शिक्षा का निजीकरण और केंद्रीकरण किया जा रहा है। गरीब विरोधी नीतियों का असर मध्यम वर्ग के छात्रों की शिक्षा पर पड़ रहा है।

धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में चुनावों की बहाली, प्रशासन में पारदर्शिता और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी छात्रों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रदर्शन को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, 'सरकार शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर रही है। छात्र संघों के चुनावों पर रोक से साफ है कि सरकार शिक्षित और जागरूक युवाओं से डरती है। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती, तो आंदोलन और बड़ा होगा और देशभर में गूंज सुनाई देगी।'

महीने भर के भीतर दूसरी बार इस तरह से अलग-अलग छात्र संगठन जंतर-मंतर पर एकत्र हुए हैं। इधर अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जागरुक छात्र अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते ही रहते हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र संगठन एकजुट हो रहे हैं, वह देश में बड़े बदलाव की आहट देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी युवा शक्ति ने आवाज उठाई है, तब सत्ताधीशों को बड़ी चोट पहुंची है। फिलहाल छात्र संगठनों ने आंदोलन बढ़ने की जो चेतावनी दी है, उसे मोदी सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि जो सवाल छात्र उठा रहे हैं, वो बेमानी नहीं हैं, न ही इनमें किसी एक पार्टी का एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। बल्कि यह समाज के समग्र विकास और युवा पीढ़ी की बेहतरी के लिए ही है। इसी बेहतरी का दावा नरेन्द्र मोदी कई बार करते रहे हैं। संकल्प, ऊर्जा, दृढ़ विश्वास, जैसे शब्दों के दोहराव अलग-अलग तरीके से करते हुए श्री मोदी कई मंचों से यह बात कह चुके हैं कि उनकी सारी नीतियां और फैसले देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं, जिसमें नयी पीढ़ी के लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। छात्रों के सामने अब केवल डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी मिलने की चिंता ही नहीं है, बल्कि उस डिग्री की राह में भी अब कई रोड़े आ रहे हैं। पेपर लीक और परीक्षाओं में कई किस्म की धांधलियां तो एक बड़ी समस्या है ही, इसके अलावा अब वैचारिक मतभेद रखने पर भी छात्र अन्याय का शिकार हो रहे हैं।

ताजा प्रकरण नयी दिल्ली से ही सामने आया है, जहां डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की एमए छात्रा को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर विश्वविद्यालय की कुलपति अनु सिंह लाठर द्वारा दिए गए भाषण की कथित रूप से आलोचना करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। खबर के मुताबिक कुलपति लाठर ने अपने भाषण में कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन 525 साल पुराना है और यह कोई नया मुद्दा नहीं है। कुलपति ने राम मंदिर की स्थापना के लिए राज्य की सराहना की और डॉ. बीआर आंबेडकर को सिफ दलित समुदाय का व्यक्ति न मानकर राष्ट्रीय व्यक्ति बनाने की बात कही थी। इस भाषण के बाद 28 जनवरी को आईसा से जुड़ी छात्रा ने कुलपति द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की थी। जिस पर 21 मार्च को प्रॉक्टोरियल बोर्ड के एक आदेश में विश्वविद्यालय ने 'अनुशासनहीनता' और संस्थान प्रमुख के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप छात्रा को छह महीने (पूर्ण शीतकालीन सेमेस्टर) के लिए निलंबित कर दिया गया है तथा इस अवधि के दौरान परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्रा को 17 फरवरी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उसे 28 फरवरी को प्रॉक्टोरल बोर्ड के साथ व्यक्तिगत बातचीत के लिए उसके माता-पिता के साथ बुलाया गया था। निलंबन आदेश में कहा गया है कि केवल छात्रा ही प्रॉक्टोरल मीटिंग में आई थी और उसके माता-पिता नहीं आए थे। प्रॉक्टोरल मीटिंग के बाद छात्रा द्वारा लिखित प्रतिक्रिया 'माफी मांगने वाली नहीं' थी।वहीं निलंबित छात्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम पहचान वाली महिला हैं। उन्होंने कहा, 'मैं अपने अंतिम सेमेस्टर में हूं और अंतिम सबमिशन मई के मध्य में होना है। यह मेरी डिग्री को एक साल के लिए बढ़ाने का एक बहुत ही सचेत प्रयास है।' पीड़ित छात्रा ने एक गंभीर सवाल उठाया है कि, 'यदि केवल सवाल पूछने के कृत्य को ही आपराधिक बना दिया जाए तो हमारे विश्वविद्यालयों को किस बात के लिए खड़ा होना चाहिए' इस मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को और बढ़ाने बल्कि प्रशासन द्वारा सभी असहमत छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने और उनकी आवाज को अनिश्चितकाल के लिए दबाने की एक जानबूझकर की गई साजिश है।'

लुकाशेंको ने सातवीं बार ली राष्ट्रपति पद की शपथ, विरोधियों से कहा- तुम्हारा कोई भविष्य नहीं

मींस्क। बेलारूस के सत्तावादी राष्ट्रपति अलेक्जेंर लुकाशेंको ने सातवीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राजधानी मिंस्क के इंडिपेंडेंस पैलेस में आयोजित समारोह में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने अपने विरोधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। 70 वर्षीय लुकाशेंको, जिन्हें पश्चिमी देश अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह कहते हैं, ने अपने भाषण में दावा किया कि बेलारूस में उन देशों से अधिक लोकतंत्र है, जो खुद को लोकतंत्र का आदर्श मानते हैं। उन्होंने अपने शासन को जनता के हितों का रक्षक बताते हुए पश्चिमी देशों और विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किया। हाल ही में हुए चुनाव में लुकाशेंको को 87 प्रतिशत वोटों से विजयी घोषित किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी धोखाधड़ी करार दिया। सरकार की कड़ी पकड़ के कारण वास्तविक विपक्षी उम्मीदवार मैदान में नहीं थे, और जो नामांकन में शामिल थे, उन्होंने लुकाशेंको की खुलकर प्रशंसा की। 2020 में विवादित चुनाव के बाद बेलारूस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें सरकार ने कठोर दमन के जरिए कुचल दिया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई विपक्षी नेता निर्वासित हो गए, और मीडिया व सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

अमेरिकी सेना ने यमन के सादा प्रांत पर हवाई हमले किये

सना। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात यमन के उत्तरी सादा प्रांत पर दो हवाई हमले किये। हूती संचालित अल-मसीरा टीवी ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों का लक्ष्य सादा के मध्य में सहर जिला था, लेकिन कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। अमेरिकी सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सादा ईरान-संबद्ध हूती आंदोलन का मुख्य गढ़ है, जिसने 2014 के अंत में गृहयुद्ध शुरू होने के बाद से राजधानी सना सहित उत्तरी यमन को नियंत्रित किया है। हवाई हमले यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्रों के खिलाफ चल रहे अमेरिकी अभियान का हिस्सा हैं, जिसे मार्च के मध्य में शुरू किया गया था। हूतियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में इजरायली स्थलों और जहाजों को निशाना बनाना जारी रखने और अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है।

उत्तरी जाम्बिया में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत

लुसाका। जाम्बिया के उत्तरी प्रांत लुआपुला में एक नाव पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य बच गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। जिले के आयुक्त गॉडफ्रे चिलाम्बवे ने 'टाइम्स ऑफ जाम्बिया' को यह कहते हुए उद्धृत किया कि दुर्घटना सोमवार सुबह कावाम्बवा जिले में लुएना नदी में तेज बहाव के कारण हुई। उस समय पीड़ित (सभी चीनी कंपनी के कर्मचारी) काम पर जा रहे थे। उनके अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नाव को चलाने के लिए इस्तेमाल की गई छड़ी टूट गई, जिससे पीड़ितों को अपने हाथों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन नाव तेज बहाव के कारण पलट गई। उन्होंने कहा कि अब तक केवल नौ शव बरामद किए गए हैं, उन्होंने कहा कि शेष शवों को निकालने में मदद के लिए गोताखोरों को घटनास्थल पर भेजा गया है।

कोकाकोला ने अमेरिका के दो प्रांतों से 10 हजार से अधिक कैन वापस मंगाए

वाशिंगटन। कोका-कोला ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रांतों इलिनोइस और विस्कॉन्सिन से अपने 10,000 से अधिक कैन को बाजार से वापस ले लिया है। इलिनोइस मिसिसिपी नदी और विस्कॉन्सिन ग्रेट लेक्स के किनारे स्थित है। कोकाकोला निर्माता कंपनी रेयेस कोकाकोला बॉटलिंग ने इनमें प्लास्टिक संदूषण की आशंका की वजह से इन्हें बाजार से वापस लेने का फैसला किया। एबीसी न्यूज चैनल की इस आशय की खबर में यह जानकारी दी गई। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार, 24 मार्च को यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इन कैन के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था।

अमेरिका ने फिलीपींस में तैनात की नई मिसाइल प्रणाली, चीन की धड़कनें बढ़ीं

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी नई मिसाइल प्रणाली (टाइफॉन मिसाइल सिस्टम) को उत्तरी फिलीपींस के लूजोन द्वीप के एक बेस पर स्थानांतरित किया है। अमेरिका के इस कदम ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी है। द वाल स्ट्रीट जनरल अखबार के अनुसार, यह मिसाइल प्रणाली 1,200 मील की दूरी तक मिसाइलों को दाग सकती है। शीतयुद्ध के बाद यह पहली बार है कि अमेरिकी सेना ने अपनी सीमाओं के बाहर इतनी लंबी दूरी के साथ एक भूमि-आधारित प्रक्षेपण प्रणाली की तैनात की है। इसके लिए चीन के प्रमुख सैन्य और वाणिज्यिक केंद्रों को निशाना बनाना बहुत आसान है। इसे एशिया में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ चीनी आक्रामकता रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला कदम माना जा रहा है।टाइफॉन मिसाइल सिस्टम को अमेरिकी सेना ने विकसित किया है। यह सिस्टम एसएम-6 और टॉमहॉक मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। इसे मुख्य रूप से सतह से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है।

70 वर्षीय अमेरिकी नागरिक का अपहरण कर 30 लाख यूरो की फिरौती मांगने वाली महिला गिरफ्तार

एजेंसी

काठमांडू। मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पोखरा पहुंचे एक अमेरिकन नागरिक का अपहरण कर 30 लाख यूरो फिरौती मांगने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल पुलिस की केन्द्रीय अनुसंधान विभाग (सीआईबी) ने मकवानपुर जिले से एक महिला को अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पोखरा पुलिस के प्रवक्ता अविनाश दीप ने बताया कि मंगलवार की शाम को पोखरा के एक होटल से 70 वर्षीय अमेरिकी बुजुर्ग नागरिक का अपहरण कर मकवानपुर में छिपा कर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने 37 वर्षीय महिला सरिता लामा को गिरफ्तार किया है। अपहृत अमेरिकी नागरिकों के घर वालों से 30 लाख यूरो फिरौती मांगने के बाद यह मामला सामने आया है। अपहृत

व्यक्ति के परिवार वालों ने काठमांडू स्थित अमेरिकी दूतावास में जानकारी देने के बाद पुलिस को इस अपहरण के बारे में पता चला और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला कर अपहृत नागरिक को सकुशल रिहा करवाया गया। पोखरा पुलिस के प्रवक्ता अविनाश दीप ने बताया कि सीआईबी की पोखरा टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस महिला के बारे में पता लगाया। अमेरिकी नागरिक को अपहरण कर मकवानपुर जिले के दुर्गम गांव में रखा गया था। फोन रिकॉर्ड और लोकेशन के आधार पर अपहरणकारी महिला को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही।

गिरफ्तारी के बाद महिला ने पूछताछ में बताया कि उस अमेरिकी नागरिक को मुक्तिनाथ जाने के लिए एक टूर गाइड की आवश्यकता थी और वह उसके पास टूर गाइड के रूप में पहुंची। लेकिन उस अमेरिकी नागरिक को मुक्तिनाथ मंदिर में दर्शन कराने ले जाने के बजाय उसे नशे की दवा खिला कर मकवानपुर के दुर्गम इलाके में ले जाकर बंधक बना कर रखी हुई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस मामले में गिरफ्तार महिला के अलावा और कौन कौन साथ में है।

इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का हमास को कड़ा संदेश, बंधकों की रिहाई न होने पर बढ़ाएंगे दबाव

एजेंसी

यरुशलम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर हमास गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता है, तो इजराइल उस पर दबाव बढ़ाने के लिए और कड़े कदम उठाएगा। संसद (नेसेट) को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, जितना अधिक हमास बंधकों को रिहा करने से इनकार करेगा, उतना ही अधिक हम उस पर दबाव बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल इसके लिए क्षेत्रीय कब्जे समेत अन्य रणनीतिक उपाय करेगा, हालांकि उन्होंने इन कदमों का पूरा विवरण नहीं दिया नेतन्याहू की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गाजा में संघर्ष जारी है और युद्धविराम की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। इजराइल का दावा है कि हमास के पास अब भी कई बंधक हैं, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में हुए हमले के बाद पकड़ लिया गया था। इजराइल ने पहले भी हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में सैन्य अभियान तेज किए हैं और हाल ही में कई इलाकों में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इस बीच, गाजा में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जहां नागरिकों को मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस संघर्ष के कारण बढ़ती मानवीय समस्याओं पर चिंता जताई है और जल्द से जल्द समाधान निकालने की अपील की है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बस और घर पर हमला, 13 लोगों की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद। बलूच लिबरेशन आर्मी (बलूचिस्तान मुक्ति सेना) के लड़ाकों ने पाकिस्तान की संघीय सरकार की नींद उड़ा दी है। लड़ाके मुल्क के बलूचिस्तान में सरकार से सीधा मोर्चा ले रहे हैं। आज बलूचिस्तान देश का सबसे अशांत प्रांत है। बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच प्रांत में बस यात्रियों और एक घर को निशाना बनाकर किए गए दो अलग-अलग हमलों में 13 और लोग मारे गए। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यूसुफ बंगहर ने बताया है कि ग्वादर में हमलावरों ने छह बस यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। सोहबतपुर में एक घर में हमला कर परिवार के सात सदस्यों की जान ले ली गई। सोहबतपुर हमले पर जिवानी थाने के एसएचओ खालिद दश्ती ने कहा कि सभी शव पासनी अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। मृतकों में महिला और तीन बच्चे भी हैं।

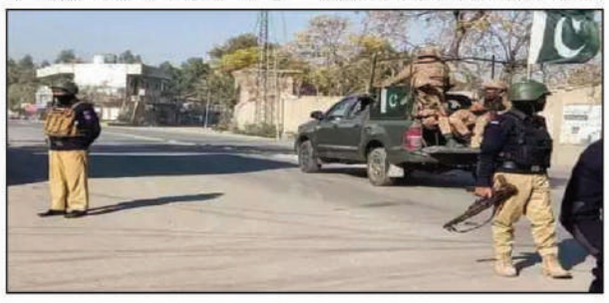

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ग्वादर हमले की निंदा की है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह कलात और नोशकी जिलों में कम से कम आठ लोगों (चार मजदूरों और चार पुलिसकर्मियों) की हत्या कर दी गई थी। हाल ही में नुश्की-दलबंदिन राजमार्ग पर अर्धसैनिक बलों के काफिले पर हुए विस्फोट में फ्रंटियर कोर (एफसी) के तीन सैनिकों सहित कम से कम पांच लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके रेलवे ट्रैक को उड़ाकर जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बंधक बना चुके हैं। संघीय सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों ने जटिल अभियान के बाद 33 लड़ाकों को मार गिराया और बंधक यात्रियों को बचाया।

आईपीएल खेलों में नेपाल से 200 करोड़ की सट्टेबाजी का खुलासा, 11 भारतीय गिरफ्तार

एजेंसी

काठमांडू। भारत में जारी आईपीएल खेलों में ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने के आरोप में पुलिस ने 11 भारतीय नागरिक को काठमांडू से गिरफ्तार किया है। जांच में अब तक यहां से 200 करोड़ रुपये की ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के प्रवक्ता एसपी सुधीर राज शाही ने मीडियाकर्मियों को बताया कि बुधवार देर रात को आईपीएल खेलों की लाइव सट्टेबाजी की सूचना मिली थी।

इसके आधार पर देर रात को काठमांडू के बूढ़ानीलकंठ इलाके में एक किराए के मकान में छापा मार कर 11 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए सभी भारतीय राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 19 से 28 साल के बीच की है। गिरफ्तार होने वालों में सन्नी मीणा (24), मोहित वर्मा (25), पीयूष भारद्वाज (26), हरकेश दादिया (25), निशांत भारद्वाज (22), आकाश वर्मा (23), अंकित कुमार सैनी (19), संजू

शुक्ला (23), राम सिंह जाट (28), लोकेश कुमार (19) और विकास कुमार (19) शामिल हैं। सीआईबी ने इस दौरान 34 मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप, हिसाब किताब रखने वाली चार रजिस्टर, भारत के अलग-अलग बैंकों के 14 चेकबुक, भारतीय बैंकों के 27 एटीएम और अलग-अलग कंपनियों के 40 भारतीय सिमकार्ड बरामद किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सट्टेबाजी के लिए वाट्सऐप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टा चैट, वी-चैट और सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीआईबी के मुताबिक इनका मास्टरमाइंड नेपाल और भारत के बाहर किसी तीसरे देश में बैठकर इन सभी को निर्देशित करता है। उस शख्स से पकड़े गए किसी भी आरोपित ने आज तक न तो मुलाकात की है और न ही उसको कोई पहचानता है।-

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर चलेगा तख्तापलट की साजिश का मुकदमा

एजेंसी

रियो डी जनेरियो। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ तख्तापलट की साजिश के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया, जिसमें बोल्सोनारो और 33 अन्य लोगों पर 2022 के चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस योजना में वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और एक सुप्रीम कोर्ट जज की हत्या करने की साजिश भी शामिल थी। कोर्ट ने बोल्सोनारो के सात करीबी सहयोगियों पर भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इन पर तख्तापलट की

कोशिश, सशस्त्र आपराधिक संगठन में शामिल होने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसक रूप से समाप्त करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और विरासत संपत्तियों को नष्ट करने के आरोप लगे हैं। बोल्सोनारो ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। हालांकि उनके वकील ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्राजील के कानून के अनुसार, यदि बोल्सोनारो तख्तापलट के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 12 साल तक की जेल हो सकती है, और अन्य आरोपों को मिलाकर यह सजा कई दशकों तक बढ़ सकती है।उल्लेखनीय है कि 08 जनवरी 2023 को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और संसद पर हमला किया था। जस्टिस फ्लावियो डिनो ने इस मामले पर कहा, तख्तापलट से मौतें होती हैं, चाहे वह आज हो या वर्षों बाद। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा और दोषियों को सजा तय करेगा।

हमास की इजराइल को धमकी, गाजा में हमले नहीं रोके तो बंधकों को मार दिया जाएगा

एजेंसी

दोहा/गाजा पट्टी। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले जारी रहे तो वह बंधकों की हत्या कर देगा। इजराइल का बलपूर्वक बंधकों को छुड़ाने का सपना पूरा नहीं होगा। अरब न्यूज के अनुसार, समूह ने आज दोहा में जारी बयान में कहा कि वह बंधकों को मारना नहीं चाहता। वह उन्हें जीवित रखने के हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इजराइल के गाजा में बरसते बम उनके जीवन को पल-पल खतरे में डाल रहे हैं।हमास ने कहा कि इजराइल ने कई बार बंधकों को बलपूर्वक वापस लेने का प्रयास किया है। हर बार उसे अपने लोगों को ताबूतों में ले जाना पड़ा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के पिछले सप्ताह शुरू हुए हमले में अब तक कम से कम 830 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के ताजा हमलों के बाद संघर्ष विराम टूट चुका है। अल जजीरा न्यूज चैनल के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गाजा पर इजराइली हमलों में कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और मलबे से एक शव बरामद किया गया है। इजराइल के सुरक्षा बल (आईडीएफ) सीरिया पर भी बम बरसा रहे हैं। इस बमबारी में डेरा में कम से कम छह लोग मारे गए हैं। कतर और सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। उधर, अमेरिका की सेना यमन पर बम बरसा रही है। इजराइल ने सात अक्टूबर, 2023 को किए गए हमलों के बाद गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था।

अमेरिका में अब आयातित कारों पर 25 फीसद टैरिफ, कीमतें बढ़नी तय

एजेंसी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब आयातित कारों और ट्रकों को 25 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में लाया गया है। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इससे इम्पोर्टेड वाहन की कीमत बढ़ने की पूरी संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिकने वाले वाहनों में से लगभग आधे आयातित होते हैं। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, नया ट्रैफिक तीन अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप की इस घोषणा का उद्देश्य अमेरिका की ऑटो विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना है। मुक्त व्यापार समझौते के कारण कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के ऑटोमेकर्स अब तक ट्रैफिक की किचकिच से दूर थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इस आशय की कार्यकारी घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले संवाददाताओं से कहा- सच कहूं तो, दोस्त अकसर दुश्मन से बहुत बुरे होते हैं। और हम जो करने

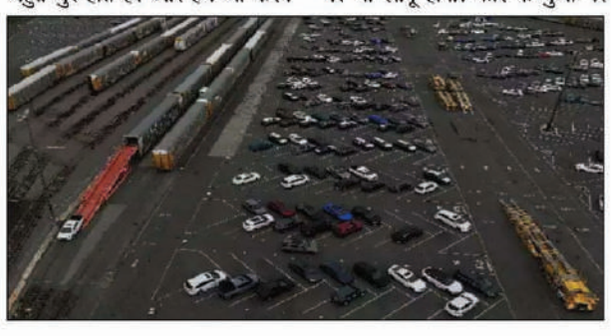

जा रहे हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनी सभी कारों पर 25 फीसद टैरिफ लगाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी कारों पर टैरिफ नहीं होगा। नया टैरिफ केवल विदेशी निर्मित कारों पर ही नहीं बल्कि इंजन और ट्रांसमिशन सहित कार के पुर्जों पर भी लागू होगा। कार के पुर्जों पर टैरिफ तीन मई से पहले लागू होगा।% ट्रंप ने कहा कि वह तीन बड़ी ऑटोमेकर कंपनियों, स्टेलेंटिस, फोर्ड और जनरल मोटर्स के संपर्क में हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रंप की घोषणा के बाद तीनों कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। जनरल मोटर्स (जीएम) के शेयरों में सात फीसद से अधिक की गिरावट आई। जीप, रैम, क्रिसलर और डॉज कारों का निर्माण करने वाली कंपनियों फोर्ड (एफ) और स्टेलेंटिस (एसटीएलए) के शेयरों में चार प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। सीएनएन के अनुसार, इस टैरिफ से महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योग को नुकसान पहुंचने का अंदेशा और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ने का खतरा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2024 में अमेरिकियों द्वारा खरीदी गई लगभग 16 मिलियन कारों, एसयूवी और हल्के ट्रकों में से आधे आयातित थे।

अमेरिका में राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित 12 बिलियन डॉलर का अनुदान रद्द

एजेंसी

वाशिंगटन,। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित लगभग 12 बिलियन डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया। यह संघीय अनुदान संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, व्यसन उपचार और अन्य जरूरी सेवाओं पर खर्च किया जा रहा था। प्रशासन ने यह पैसा कोविड-19 महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को आवंटित किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन की खबरों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। संघीय विभाग और राज्यों के कई अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम की पुष्टि की। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का कहना है कि कोविड महामारी अब खत्म हो चुकी है। करदाताओं के इस पैसे को अब बर्बाद नहीं किया जाएगा। प्रशासन को लगभग 30 दिनों में यह पैसा वापस आने की उम्मीद है। नेशनल एसोसिएशन

ऑफ काउंटी एंड सिटी हेल्थ ऑफिशियल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोरी ट्रेमेल फ्रीमैन ने कहा कि इस सप्ताह स्थानीय स्वास्थ्य विभागों और संगठनों को फंडिंग में इस समाप्ति के बारे में नोटिस भेजे गए थे। मिनेसोटा स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य को 226 मिलियन डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ था। गैर लाभकारी संस्था डे ब्यूमोंट फाउंडेशन के अध्यक्ष और सीईओ ब्रायन कैस्ट्रुची ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक विनाशकारी झटका है। टेक्सास में डलास स्वास्थ्य और मानव सेवा के निदेशक डॉ. फिलिप हुआंग ने कहा कि इस कदम से महामारी विज्ञान, संपर्क अनुरेखण और प्रयोगशाला परीक्षण प्रभावित होंगे। स्थानीय सामुदायिक केंद्रों में मधुमेह शिक्षा कार्यक्रमों जैसे प्रयासों पर भी असर पड़ेगा।

आधिपत्यवादी सोच न थोपे अमेरिका : चीन

बीजिंग। चीन ने अमेरिका से अपनी आधिपत्यवादी सोच को उस पर न थोपने का आग्रह किया है और कहा कि चीन-अमेरिका संबंधों को शीत युद्ध की पुरानी मानसिकता से न देखे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को बीजिंग में अमेरिका की एक रिपोर्ट में चीन को अपने शीर्ष सैन्य और साइबर खतरे के रूप में बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हुए ये बातें कहीं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिका हर साल इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना और पक्षपाती रिपोर्ट जारी करता है, जिससे चीन खतरा जैसी धारणाएं फैलाई जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इन रिपोर्ट का इस्तेमाल बड़े देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, चीन को दबाने और अपने वैश्विक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए करता है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान मुद्दा पूरी तरह से उसका आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन 'ताइवान स्वतंत्रता' का विरोध करने और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश इसे हल्के में न ले या गलत अनुमान न लगाए। श्री जियाकुन ने अमेरिका से आग्रह किया कि वह अपनी आधिपत्यवादी सोच को चीन पर न थोपे और चीन-अमेरिका संबंधों को शीत युद्ध की पुरानी मानसिकता से न देखे।

एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण विपक्षी दलों ने किया संसद अवरुद्ध

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल सरकार द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने के कारण विपक्षी दलों ने दिनभर संसद को अवरुद्ध रखा है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के तरफ से स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए सदन की कारवाई नहीं चलने दी। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग को पदमुक्त करने के निर्णय के विरोध में विपक्षी दलों ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। प्रमुख विपक्षी दल माओवादी सहित एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय जनमोर्चा और नेपाल मजदूर किसान पार्टी ने सामूहिक रूप से सदन को अवरुद्ध किया है। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ने सदन में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग की बर्खास्तगी पर प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देने की मांग की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अपने स्थान पर ही खड़े होकर स्पीकर से सदन की कार्रवाई नहीं चलाने और प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा

कि जब तक सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री ओली स्वयं सदन में आकर जवाब नहीं देते तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं चलने दी जाएगी। विपक्षी दलों के द्वारा सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई अवरुद्ध करने के कारण स्पीकर देवराज घिमिरे ने पहले सदन की कार्रवाई को 10 मिनट और फिर बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्षी दल के प्रमुख सचेतकों की बैठक बुलाई लेकिन सत्तापक्ष के तरफ से एमाले पार्टी के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने कहा कि विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक की बर्खास्तगी पर प्रधानमंत्री को सदन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दलों को जवाब ही चाहिए तो ऊर्जा मंत्री आकर सदन में जवाब दे सकते हैं। लेकिन सत्तापक्ष के जवाब से विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देने की बात पर अडिग रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन की कार्रवाई को चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाने के बाद स्पीकर घिमिरे ने वृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित होने की सूचना प्रकाशित कर दी। विपक्षी दलों ने कल भी प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा दोनों सदनों की कार्रवाई को नहीं चलने देने की बात दोहराई है।

गुज्जर और बक्करवालों के लिए अंतर-ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित

एजेंसी

रियासी। सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और खेल भावना को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास में भारतीय सेना ने जिला रियासी के बलमतकोट के सुदूर स्थान पर गुज्जर और बक्करवाल समुदाय के लिए अंतर-ग्राम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई गांवों से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई जिसमें युवा एथलीटों ने अपनी प्रतिभा, टीमवर्क और खेल भावना का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करना, सामुदायिक बंधनों को मजबूत करना और स्थानीय युवाओं को खेलों में अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। भाग लेने वाली टीमों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हुए जिससे यह कार्यक्रम शानदार सफल रहा। भारतीय सेना ने समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी की जिससे सुदूर क्षेत्रों के कल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बल मिला। विजेता टीम को क्षेत्र में खेल गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए पदक और खेल उपकरण प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का समापन एकता के संदेश और भारतीय सेना द्वारा गुज्जर और बक्करवाल समुदाय के युवाओं के लिए इस तरह की पहल का समर्थन जारी रखने के आश्वासन के साथ हुआ।

भारतीय निशानेबाजों का पहला दल अर्जेंटीना के लिए रवाना

नई दिल्ली। भारतीय निशानेबाजों का 22 सदस्यीय पहला दल सुबह अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना हो गया है। दल में 13 सहायक स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। भारतीय निशानेबाज 2025 के पहले अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप (राइफल/पिस्टल/शॉटगन) में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धाएं 03 अप्रैल से शुरू होंगी। कुल 35 भारतीय निशानेबाज 15 पदक आयोजनों में भाग लेंगे, जिसमें 12 व्यक्तिगत और 03 मिश्रित टीम इवेंट्स शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में दोहरी पदक विजेता मनु भाकर एकमात्र एथलीट हैं जिन्हें दो व्यक्तिगत इवेंट्स में चयनित किया गया है। शेष टीम के सदस्य 29 मार्च को रवाना होंगे, क्योंकि उनकी प्रतियोगिताएं टूर्नामेंट के बाद के चरणों में शुरू होती हैं। कुछ को छोड़कर सभी निशानेबाजों ने 14 मार्च से दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय रचनात्मकता शिविर में भाग लिया था, जो दक्षिण अमेरिका में होने वाले दोहरे वर्ल्ड कप चरण की तैयारी कर रहे थे। ब्यूनस आयर्स के बाद पेरू के लीमा में अगले महीने दूसरा वर्ल्ड कप होगा। इससे पहले भारतीय निशानेबाजी टीम के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर रौनक पांडे ने शिविर की प्रमुखता के बारे में बात करते हुए कहा, हमारा मुख्य ध्यान हर एथलीट की क्षमता को अधिकतम बनाने पर है।

हिला क्रिकेट विश्व कप 2025 क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान की टीम घोषित, निदा डार बाहर

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 क्वालिफायर के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 9 से 19 अप्रैल तक पाकिस्तान में खेला जाएगा, जिसमें मेजबान पाकिस्तान सहित छह टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट के शीर्ष दो स्थानों पर रहने वाली टीमें इस साल भारत में होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। टीम की कप्तानी फातिमा सना करेंगी, जो पिछले साल आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भी पाकिस्तान की कप्तान रही थीं। हालांकि, टीम से बॉलिंग ऑलराउंडर निदा डार को बाहर रखा गया है। निदा उन 19 खिलाड़ियों में शामिल थीं, जिन्हें इस क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया था, लेकिन अंतिम टीम में उन्हें जगह नहीं मिल पाई। इस टीम में युवा बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार की भी वापसी हुई है, जो 2023 में कंधे की चोट के कारण क्रिकेट से दूर रही थीं। यह छह टीमों का क्वालिफायर टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मैच खेलेंगी। शीर्ष दो टीमें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो इस साल भारत में होगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं।

लियोनेल मेसी 14 साल बाद आएंगे भारत

नई दिल्ली। फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14 साल बाद लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम भारत का दौरा करने वाली है। अक्टूबर 2025 में केरल के कोच्चि में अर्जेंटीना एक प्रदर्शनी मैच खेलेगी। एचएसबीसी इंडिया ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत भारत में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस करार के तहत अर्जेंटीना की टीम भारत का दौरा करेगी और एक दोस्ताना मुकाबला खेलेगी।एचएसबीसी इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, इस साझेदारी के तहत अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम, जिसमें दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भी शामिल हैं, अक्टूबर में भारत का दौरा करेगी और एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी मैच खेलेगी। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष क्लाउडियो फेबियन टापिया ने इस करार को अपनी टीम के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक नया मील का पत्थर बताया। यह समझौता भारत और सिंगापुर में अर्जेंटीना की फुटबॉल उपस्थिति को मजबूत करेगा।

केआईपीजी 2025 (राउंडअप-सातवां दिन): सोनलबेन ने टेबल टेनिस में जीता स्वण

एजेंसी

नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के सातवें दिन गुजरात की पैरा ओलंपियन सोनलबेन पटेल ने महिलाओं की क्लास 3 टेबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने बिहार की विद्या कुमारी को आसानी से हराकर खिताब पर कब्जा किया।इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए अन्य टेबल टेनिस फाइनल मुकाबलों में 21 वर्षीय रिषिता नथवानी और 14 वर्षीय दीपिका विजय ने पुरुषों की क्लास 5 और महिलाओं की क्लास 4 श्रेणी में चौंकाने वाली जीत दर्ज की।

पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के सातवें दिन के समापन तक 178 स्वर्ण पदक तय हो चुके थे। हरियाणा 32 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि तमिलनाडु (28 स्वर्ण) और उत्तर प्रदेश (22 स्वर्ण) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

सोनलबेन पटेल का संघर्ष और सफलता की कहानी

37 वर्षीय सोनलबेन पटेल जब केवल छह महीने की थीं, तब उन्हें पोलियो हो गया था, जिससे उनके दोनों पैर और दाहिना हाथ प्रभावित

हुआ और 90त्न दिव्यांगता हो गई। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। अपनी जीत के बाद सोनलबेन ने कहा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में न सिर्फ भाग लेना बल्कि लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतना अविश्वसनीय अनुभव है। मैंने कभी अपनी दिव्यांगता को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया, और इस पर मुझे गर्व है। तीन दिनों तक चली पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। जसप्रीत कौर (45 किग्रा), मनीष कुमार (54 किग्रा), सीमा रानी (61 किग्रा) और झांडू कुमार (72 किग्रा) ने अपने-अपने भार वर्ग में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। हरियाणा के प्रदीप जून ने 107+ किग्रा भार वर्ग में 194 किग्रा वजन उठाकर लगातार दूसरी बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का स्वर्ण पदक जीता। प्रदीप, जो एक किसान परिवार से आते हैं, ने 2021 में पावरलिफ्टिंग शुरू की थी और अब वे राष्ट्रीय खेलों और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण जीत चुके हैं। अपनी कठिन यात्रा को याद करते हुए प्रदीप ने कहा, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी एक हादसे में मेरी टांग में नसों को नुकसान पहुंचा। सही इलाज न मिलने के कारण मेरी टांग काटनी पड़ी। मैं छह महीने तक अवसाद में रहा, लेकिन मेरे दोस्त जयदीप ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे पावरलिफ्टिंग से जोड़ा, जिससे मुझे नई पहचान मिली।दिल्ली की सहिस्ता ने भी शानदार प्रदर्शन किया और पिछले संस्करण की रजत पदक विजेता इस बार 79 किग्रा भार वर्ग में 81 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। बचपन में एक गलत इंजेक्शन के कारण उनके घुटने को स्थायी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला। अपनी उपलब्धि पर सहिस्ता ने कहा, मैंने समय के साथ इसे स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री ने सेपक टाकरा विश्वकप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने पर पुरुष रेगु टीम को बधाई दी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेपक टाकरा विश्वकप 2025 में भारतीय सेपक टाकरा दल को उनके अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए पहला स्वर्ण पदक लाने पर टीम की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, सेपक टाकरा विश्वकप 2025 में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए हमारे दल को बधाई। यह दल 7 पदक लेकर आया है।

पुरुषों की रेगु टीम ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह शानदार प्रदर्शन वैश्विक सेपक टकरा के खेल में भारत के लिए आशाजनक भविष्य का संकेत देता है। उल्लेखनीय है कि पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा विश्वकप 2025 में भारत की पुरुष रेगु टीम ने मंगलवार को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। भारत ने फाइनल में जापान पर 2-1 से जीत हासिल की।

फीफा क्लब विश्व कप 2025 की पुरस्कार राशि घोषित: विजेता को 125 मिलियन डॉलर!

एजेंसी

नई दिल्ली। फीफा ने 2025 क्लब वर्ल्ड कप की इनामी राशि का खुलासा कर दिया है, जिससे यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे अधिक पुरस्कृत क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता बन गया है।

मुख्य इनामी राशिः

विजेता टीमः 125 मिलियन डॉलर तक जीतने का मौका।

कुल इनामी राशिः 1 बिलियन डॉलर की राशि 32 प्रतिभागी क्लबों में वितरित की जाएगी।

अतिरिक्त सहायताः वैश्विक क्लब फुटबॉल को समर्थन देने के लिए 250 मिलियन डॉलर अलग रखे गए हैं।

भागीदारी इनामी राशिः 525 मिलियन डॉलर निर्धारित।

क्षेत्रीय आधार पर इनामी राशिः

यूईएफए क्लबः 12.81 मिलियन डॉलर से 38.19 मिलियन डॉलर तक की राशि प्राप्त करेंगे, जो उनकी रैंकिंग और राजस्व पर निर्भर करेगा। चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख जैसी टीमें शीर्ष इनामी राशि पाने की दावेदार हैं।

कोंमेबोल (दक्षिण अमेरिकी) क्लबः 15.21 मिलियन डॉलर के करीब।

कॉनकैकएएफ, सीएएफ और एएफसी क्लबः 9.55 मिलियन डॉलर।

ओएफसी (ओशिनिया) क्लबः 3.58 मिलियन डॉलर।

टूर्नामेंट का प्रारूपः

टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग लेंगी।

प्रतियोगिता 14 जून से 13 जुलाई, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगी।

इसमें सात मैचों का ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ फॉर्मेट होगा।

टूर्नामेंट से होने वाली सभी कमाई क्लब फुटबॉल के विकास में ही लगाई जाएगी।

फीफा की नई वैश्विक फुटबॉल पहलः

फीफा ने सॉलिडैरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की भी घोषणा की है, जिससे फुटबॉल का वैश्विक स्तर पर विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से, फीफा इस टूर्नामेंट से कोई राजस्व नहीं रखेगा और उसकी आरक्षित निधि भी प्रभावित नहीं होगी, जिससे 211 सदस्य संघों में फुटबॉल का दीर्घकालिक निवेश सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मैं बल्लेबाज की तरह सोचता हूं, यही मेरी ताकत है- मोईन अली

एजेंसी

गुवाहाटी। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के ऑलराउंडर मोईन अली ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन से टीम को पहली जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2 विकेट लेकर 23 रन दिए और खासकर नितीश राणा को क्लासिक ऑफ-स्पिन गेंद से बोल्ड कर सबका ध्यान खींचा।पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोईन अली ने अपनी गेंदबाजी की रणनीति पर बात करते हुए कहा, मैं हमेशा बल्लेबाज की तरह सोचता हूं, यही मेरी ताकत है।

इससे मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि सामने वाला बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहा है। केकेआर को अपने प्रमुख स्पिनर और पिछले सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नारायण की गैरमौजूदगी में एक असरदार गेंदबाज की जरूरत थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोईन अली पर भरोसा जताया और उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट लेकर 23 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती (2/17) की किफायती गेंदबाजी के साथ, मोईन अली ने भी शानदार स्पिन आक्रमण किया और राजस्थान रॉयल्स को गुवाहाटी में 151/9 के स्कोर पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोईन ने इस मुकाबले में खुद को 'दूसरे स्पिनर' की भूमिका में सहज बताया और कहा कि यह भूमिका उन्हें हमेशा पसंद रही है। मोईन अली ने कहा, मैं वरुण से पहले गेंदबाजी करने आया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जितना हो सके कसी हुई गेंदबाजी करूं, ताकि वह दबाव बना सकें और विकेट निकाल सकें। मैं हमेशा ऐसे स्पिनर के साथ गेंदबाजी करता रहा हूं, जो मुझसे बेहतर होता है और जिसके पास मुझसे ज्यादा विविधताएं होती हैं। इसलिए मेरी भूमिका यही रहती है कि मैं रन रोकूं और दूसरे गेंदबाज के लिए विकेट लेने का मंच तैयार करूं। मोईन अली ने यशस्वी जायसवाल का विकेट चटकाया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नितीश राणा को क्लासिक ऑफ-स्पिन डिलीवरी पर बोल्ड किया, वह सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह गेंद वास्तव में अच्छी थी। मैंने बस सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने और उसे जितना संभव हो सके स्पिन कराने की कोशिश की। मेरी ताकत यह है कि मैं एक बल्लेबाज की तरह सोचता हूं, जिससे मुझे यह अंदाजा रहता है कि सामने वाला बल्लेबाज क्या सोच रहा होगा।

आईपीएल 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर दर्ज की पहली जीत

एजेंसी

गुवाहाटी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के छठे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को आठ विकेट से हराया। यह मैच असम के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां केकेआर ने इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 151/9 का स्कोर खड़ा किया। ध्रुव जुरेल (33), यशस्वी जायसवाल (29) और कप्तान रियान पराग (25) ने उपयोगी पारियां खेलीं, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने उन्हें बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मोईन अली और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार

गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 17.3 ओवर में केवल दो विकेट खोकर 153 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के हीरो रहे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने नाबाद 97 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने 61 गेंदों पर आठ चौके और छह छक्के लगाए। उनके अलावा अंगकृष रघुवंशी ने 22 रन बनाए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 18 और मोईन अली ने पांच रन जोड़े। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह लगातार दूसरी हार रही। टीम को अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ 44 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ केकेआर ने आईपीएल 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है।

सचिवालय चैंपियंस ट्रॉफी 2025 : डेंजर और लायंस ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

देहरादून। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सचिवालय चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतिम दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में सचिवालय डेंजर ने रोमांचक जीत दर्ज की, जबकि दूसरे मैच में लायंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

पहला क्वार्टर फाइनलःडेंजर बनाम बुल्स

पहले मुकाबले में सचिवालय डेंजर और सचिवालय बुल्स की टीमें आमने-सामने थीं। पहले बल्लेबाजी करते हुए डेंजर ने 108 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। अरविंद राणा ने 34 रन की अहम पारी खेली। बुल्स की ओर से अमीन सिंह ने 3 और मुकेश रावत ने 2 विकेट चटकाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय बुल्स की टीम 99 रन पर सिमट गई और 9 रन से मुकाबला हार गई। राजेश वर्मा ने 37 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। डेंजर के लिए नीरज और फाजिल ने 2-2 विकेट लिए। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए फाजिल को मैन ऑफ द मैच, जबकि संघर्षपूर्ण पारी के लिए राजेश वर्मा को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया।

अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश

एजेंसी

मुंबई। बॉम्बे जिमखाना में हुए रोमांचक मुकाबलों में अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह भारत का पहला पीएसए कॉपर टूर्नामेंट है और इसमें एक अनोखा मोड़ देखने को मिला जब मुकाबले बॉम्बे जिमखाना के लॉन पर बने आउटडोर ग्लास कोर्ट में खेले गए। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले भी इसी कोर्ट पर खेले जाएंगे। भारत की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी और जेएसडब्ल्यू की समर्थित अनाहत सिंह को जब वह अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए कोर्ट में उतरीं तो दर्शकों की जोरदार चीयरिंग सुनाई दी। उनका मुकाबला मिस्र की नादिन एल्हम्मामी से था। अनाहत ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले गेम में पूरी तरह हावी रहीं। लेकिन एल्हम्मामी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम टाई-ब्रेक तक ले जाकर

जीत लिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा गेम भी जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, घरेलू दर्शकों के समर्थन से अनाहत ने चौथा गेम जीतकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन 17 वर्षीय अनाहत ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जोशना चिनप्पा का मुकाबला शाम के सत्र में शीर्ष वरीयता प्राप्त अकांक्षा सालुंखे से हुआ। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने एक-दूसरे के खेल को अच्छे से समझते हुए जोरदार टक्कर दी। चिनप्पा ने पहले दो गेम बेहद करीबी अंतर से जीते, लेकिन सालुंखे ने शानदार वापसी करते हुए दो गेम जीतकर मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। 56 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में अंततः चिनप्पा ने 3-2 (12-10, 13-11, 9-11, 9-11, 11-5) से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पुरुष वर्ग में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के अमीशेनराज चंद्रन के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया। अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए अभय ने शुरू से ही मैच पर नियंत्रण बनाए रखा और अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने केवल 34 मिनट में 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में जैकब डफी की बड़ी छलांग, टॉप-5 गेंदबाजों में पहुंचे

दुबई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी की आईसीसी मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में जबरदस्त उछाल जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद डफी ने सात स्थानों की छलांग लगाकर टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में पांचवें स्थान (694 रेटिंग अंक) पर कब्जा कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ताजा पुरुष टी20 रैंकिंग जारी की, जिसमें डफी ने अपनी स्थिति और मजबूत की। पिछले हफ्ते उन्होंने 23 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई थी और अब लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते वह करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तक पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो मैचों में कुल छह विकेट चटकाए थे।

युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिपः स्टीलर्स और पिंक कब्स की बड़ी जीत, युवा पलटन ने बनाए रखी उम्मीदें

एजेंसी

हरिद्वार। वंदना कटारिया इंडोर स्टेडियम में जारी युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप में रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें जूनियर स्टीलर्स, जयपुर पिंक कब्स, युवा पलटन और पलानी टस्कर्स ने शानदार जीत दर्ज की।

स्टीलर्स ने वाइपर्स को दी करारी शिकस्त

दिन के पहले मुकाबले में जूनियर स्टीलर्स ने वास्को वाइपर्स को 63-26 से हराया। पहले हाफ में स्टीलर्स ने दो ऑल-आउट और एक सुपर रेड के दम पर 32-12 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में उन्होंने दो और ऑल-आउट कर मुकाबले को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया। जया सूर्या 18 अंकों के साथ मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। स्टीलर्स अब 33 अंकों के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर हैं, जबकि वाइपर्स 14 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर हैं।

जयपुर पिंक कब्स की शानदार जीत

दूसरे मुकाबले में जयपुर पिंक कब्स ने यूपी फाल्कन्स को 50-33

के बड़े अंतर से हराया। पहले हाफ तक कब्स ने 27-15 की बढ़त बना ली थी। मैच के दौरान परविंदर ने 16 अंक और के. धरनीधरन ने 13 अंक जुटाए। जयपुर पिंक कब्स अब 73 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर हैं, जबकि फाल्कन्स 33 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

युवा पलटन की उम्मीदें बरकरार

तीसरे मुकाबले में युवा पलटन ने कुरुक्षेत्र वॉरियर्स को 50-33 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखीं। अजय गुलिया और करमबीर ठाकुर ने 10-10 अंक अर्जित किए। युवा पलटन अब 31 अंकों के साथ पूल बी में पांचवें स्थान पर है।

पलानी टस्कर्स की करीबी जीत

दिन के अंतिम मुकाबले में पलानी टस्कर्स ने चंडीगढ़ चार्जर्स को 36-33 से हराया। मोहित सुरेंद्र 15 अंकों के साथ बेहतरीन खिलाड़ी रहे। चार्जर्स 42 अंकों के साथ पूल बी में चौथे और टस्कर्स 41 अंकों के साथ पूल ए में तीसरे स्थान पर हैं।

खेलो इंडिया पैरा गेम्सः पावरलिफ्टिंग में परदीप जून और शाइस्ता चमके, एकता भ्यान ने टेबल टेनिस में जीता स्वर्ण

एजेंसी

नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के सातवें दिन पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां कई पूर्व पदक विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। तीन दिनों की इस स्पर्धा में चार नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें जसप्रीत कौर (45 किग्रा), मनीष कुमार (54 किग्रा), सीमा रानी (61 किग्रा) और झांडू कुमार (72 किग्रा) ने इतिहास रच दिया।अब तक के मुकाबलों में 170 स्वर्ण पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। पदक तालिका में हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर है, जबकि तमिलनाडु (26) और उत्तर प्रदेश (22) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

पावरलिफ्टिंग में परदीप और शाइस्ता की स्वर्णिम जीत

हरियाणा के परदीप जून ने 107+ किग्रा वर्ग में 194 किग्रा भार उठाकर लगातार दूसरी बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। परदीप, जो पहले खेती में काम करते थे, एक दुर्घटना के कारण अपने पैर की नसों को नुकसान पहुंचा बैठे, जिससे अंततः उनका पैर काटना पड़ा। छह महीने तक अवसाद में रहने के बाद, उनके मित्र जयदीप ने उन्हें पावरलिफ्टिंग से परिचित कराया। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता था। दिल्ली की शाइस्ता ने भी अपनी पिछली बार की रजत पदक जीत को इस बार स्वर्ण में बदला। 79 किग्रा वर्ग में उन्होंने 81 किग्रा भार उठाकर शानदार जीत दर्ज की। बचपन में एक गलत इंजेक्शन से उनके घुटने को स्थायी क्षति पहुंची थी। शाइस्ता ने बताया, पहले मैं सिर्फ मांसपेशियां बनाना चाहती थी, लेकिन पावरलिफ्टिंग मेरा जुनून बन गई। अब मेरा लक्ष्य पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है।

टेबल टेनिस में एकता भ्यान का स्वर्णिम प्रदर्शन

इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा के रोमांचक मुकाबलों के बीच हरियाणा की एकता भ्यान ने क्लास 1 और 2 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने तमिलनाडु की दीपिका रंज रामनाथन को 3-2 से हराया।

एकता, जो 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में क्लब थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक विजेता रही हैं, ने क्लब थ्रो के पेरिस 2024 से बाहर होने के बाद टेबल टेनिस में कदम रखा।

अपनी जीत के बाद उन्होंने कहा, यह मेरा पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था और मैं आयोजकों की सराहना करती हूं। उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा से हमें अपनी मेहनत का सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है।हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, जहां कई युवा खिलाड़ी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने की ओर अग्रसर हैं।

Stree 3 आई भी नहीं और खुल गया सबसे बड़ा राज, ये है

श्रद्धा कपूर

के किरदार का नाम

स्त्री 2 हिन्दी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है. इस फिल्म के बाद से श्रद्धा कपूर के दीवानों की लिस्ट में खूब इजाफा हुआ. स्त्री में श्रद्धा के रोल को लेकर एक बड़ा सस्पेंस था. स्त्री 2 में ये सस्पेंस कुछ हद तक खत्म हुआ और पता चला कि श्रद्धा का किरदार असल में स्त्री की बेटी है जो खुद भी मर चुकी है, और वो अपनी मां के कातिलों से बदला लेने के लिए आई है. लेकिन फिल्म का एक सस्पेंस ऐसा भी है जो अबतक खत्म नहीं हो पाया है.

स्त्री में श्रद्धा के किरदार के नाम की एक अलग ही मिस्ट्री है. हर किसी को जानना है कि श्रद्धा कपूर के किरदार का नाम आखिर क्या है. ऐसा क्या है जो वो विकी के कान में कहती

है. लेकिन अब इस राज से भी पर्दा उठ गया है. श्रद्धा के किरदार का नाम लीक हो गया है.

ये है श्रद्धा के किरदार का नाम

स्त्री फ्रेंचाइज की दो फिल्में अब तक आ चुकी हैं, तीसरे की भी तैयारी है, लेकिन फिल्म में श्रद्धा के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई है. दरअसल सोशल मीडिया पर जो स्क्रिप्ट वायरल हो रही है वो 'स्त्री 3' की बताई जा रही है. हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक श्रद्धा कपूर का नाम गायत्री बताया जा रहा है. अगर आप विकिपीडिया पर चेक करेंगे तो उसपर भी श्रद्धा का नाम गायत्री ही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थ्योरीज

अब लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर जमकर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और काफी लोग इसको फेक भी बता रहे हैं. हालांकि काफी लोगों का कहना है की स्क्रिप्ट अगर सच भी हुई तो इसको मेकर्स बदल देंगे, क्योंकि नाम रिवील हो गया है. इसके अलावा श्रद्धा के नाम के लीक होने के बाद से कई फैन थ्योरीज भी सोशल मीडिया पर चल रही है. एक थ्योरी के मुताबिक, अगर श्रद्धा का नाम वाकई गायत्री है तो इसका मतलब है कि वो इस यूनिवर्स में बहुत ही अलग तरह का डीवाइन किरदार हो सकती है. खैरज श्रद्धा का फिल्म में असल में क्या किरदार है और उसका नाम क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

1 लाख की भीड़... सोनू निगम के साथ लाइव कॉन्सर्ट में हुआ बड़ा 'हादसा', लोगों ने फेंके पत्थर

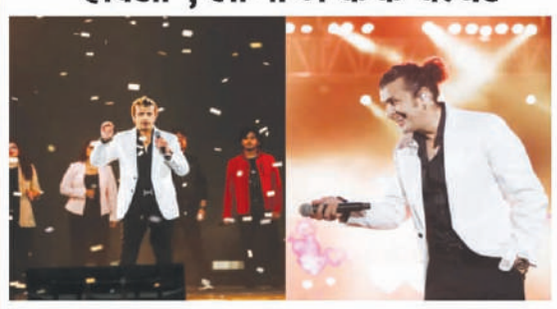

हिंदी सिनेमा के पॉपुलर सिंगर सोनू निगम की आवाज का जादू हर किसी पर चलता है. बच्चे हो या बूढ़े या फिर आज की जनरेशन हो सोनू निगम अपनी सुरीली और मखमली आवाज से हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं. सोनू जहां भी जाते हैं वहां उनकी एक झलक के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ती है.सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है. हालांकि हाल ही में सोनू के एक लाइव शो के दौरान दुखद घटना घट गई. सोनू निगम के शो में कुछ फैंस ने बोतलें फेंकी तो किसी ने पत्थर भी फेंके. ये सब देखकर सोनू उनसे शांत होने की अपील करते रहे. हालांकि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई. लेकिन सोनू ने इस घटना के चलते बीच में ही परफॉर्मेंस रोक दी थी.

लाइव कॉन्सर्ट में सोनू पर फेंके गए पत्थर

सोनू निगम ने हाल ही में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) के 'इंजीफेस्ट 2025' में हिस्सा लिया था. बताया जा रहा है कि सोनू निगम को सुनने के लिए एक लाख छात्रों की भीड़ मौजूद थी. सिंगर की परफॉर्मेंस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने स्टेज पर पत्थर और बोतले फेंकी. सोनू ने ऐसे में शो को रोक दिया.

सोनू ने फैंस से की ये अपील

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू निगम ने इसके बाद फैंस से अपील करते हुए इस तरह की चीजें न करने के लिए कहा. सोनू ने कहा, मैं आपके लिए आया हूं यहां पे, ताकि हम सब अच्छा समय बिता सकें. मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप एन्जॉय न करें, लेकिन प्लीज ऐसा न करें.

सोनू के लाइव कॉन्सर्ट में क्यों बिगड़े हालात

सोनू ने रविवार की रात को ये कॉन्सर्ट किया था. इसमें फैंस की भारी भीड़ मौजूद थी. शुरुआत में एक फैन ने सोनू की तरफ पिंक हेडबैंड फेंका तो सिंगर ने उसे पहन लिया. इस दौरान वो अपना सुपरहिट सॉन्ग 'तुमसे मिलके दिल का जो हाल' गा रहे थे. लेकिन इसके बाद हालात बिगड़ने लगे और स्टेज पर स्टूडेंट्स ने पत्थर, बोतले भी फेंकी. स्टूडेंट्स ने ऐसा क्यों किया इसे लेकर तो कोई जानकारी नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि छात्रों ने इसकी शुरुआत मस्ती और उत्साह में की थी लेकिन देखते देखते हालात बिगड़ गए और मामले ने भयावह रूप ले लिया. लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ.

हादसे में बाल बाल बचीं सोनू सूद की वाइफ सोनाली, कितने दिन रहेंगी अस्पताल में एडमिट?

एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद की कार का बीती रात एक्सीडेंट हो गया. ये हादसा तब हुआ जब वे सफर पर थीं और उनकी गाड़ी नागपुर हाईवे पर आगे बढ़ रही थी. इस दौरान कार में उनके साथ उनकी बहन और भांजा भी था. भांजा कार चला रहा था और उसी वक्त अचानक से ये हादसा हुआ. हादसे के वक्त की कुछ तस्वीरें भी आई हैं जिसमें कार के चिथड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भयंकर था. मगर सोनू सूद की फैमिली बाल-बाल बच गईं. इसके बाद से ही फैंस अपने फेवरेट हीरो की फैमिली के लिए दुआएं कर रहे हैं. अब सोनाली सूद को लेकर हेल्थ अपडेट आ गई है.ANI की रिपोर्ट्स की मानें तो सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद उनकी बहन और भतीजे को बीती रात लगभग 10:30 बजे नागपुर के मैक्स अस्पताल में एडमिट किया गया. दोनों को एमर्जेंसी में लाया गया. जब तीनों मरीज को अस्पताल लाया गया तो वे होश में थे. उन्हें कई खरोंचें लगी थीं और आंतरिक चोट के लिए उनकी गहन जांच भी की गई है. रिपोर्ट में आंतरिक चोटें नहीं आई हैं जो सोनू सूद की फैमिली के लिए राहत की बात है. उनके भतीजे को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद और उनकी बहन मौजूदा समय में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है.

सोनू सूद ने टीवी 9 से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी पत्नी की गाड़ी का एक्सिडेंट हुआ था, मगर शुक्र की बात ये है कि सोनाली चमत्कारिक ढंग से बच गईं हैं. सोनाली और उनकी बहन को अभी 2-3 दिन तक अस्पताल में रखा जा सकता है. एक्टर के लिए खुशी की बात ये है कि दोनों बड़े हादसे का शिकार होने से बच गईं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है. सोनू सूद की वाइफ लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और वे फिल्म इंडस्ट्री से भी दूरी बनाकर रखती हैं. सोनू ने 25 सितंबर 1996 को सोनाली से लव मैरिज की थी. इस शादी से उन्हें दो बेटे है जिनके नाम अयान और एहसान सूद है. बॉलीवुड एक्टर अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहते हैं.

युवाओं में है दीपिका पादुकोण

शिल्पा शेट्टी

की तरह दिखने की होड़, कॉस्मेटोलॉजिस्ट शगुन गुप्ता का खुलासा

एक समय था जब बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस कोस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने चेहरे का ट्रीटमेंट कराती थीं. हालांकि तब सिर्फ लग्जरी मानी जाने वाली ये प्रक्रिया अब लोगों के लिए जरूरत बन गई है. हाल ही में हमने सेलिब्रिटी कॉस्मेटोलॉजिस्ट, पर्मनंट मेकअप आर्टिस्ट और स्किन केयर स्पेशलिस्ट शगुन गुप्ता के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से इन दिनों युवाओं में शिल्पा शेट्टी और दीपिका पादुकोण की तरह दिखने का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है. कई बार उनके पास ऐसे लोग आते हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह बॉडी फीचर चाहते हैं.

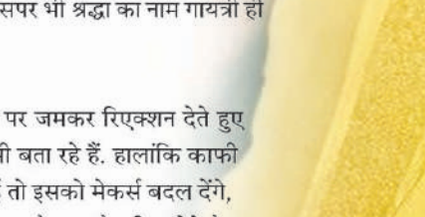

शगुन गुप्ता ने कहा, मेरे पास सबसे ज्यादा लोग ये डिमांड लेकर आते हैं कि उन्हें दीपिका पादुकोण की तरह होंठ और आइब्रो चाहिए. शिल्पा शेट्टी को लेकर भी लोगों का ऑब्सेशन है. उन्हें उनकी तरह दिखना होता है, उनकी तरह आइब्रो चाहिए होती है, उनकी तरह शक्ल चाहिए होती है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें प्रियंका चोपड़ा की तरह दिखना है. हालांकि हम उन्हें ये समझाते हैं कि उनके चेहरे पर क्या शोभा देगा, दीपिका और शिल्पा के खूबसूरत फीचर उनके चेहरे पर शायद भद्दे लग सकते हैं और इसलिए हम उन्हें सही गाइड करते हैं कि उन्हें अपने चेहरे पर क्या कराना होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए.

लोगों को है ग्रूमिंग की जरूरत

शगुन गुप्ता ने बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी से करेक्शन करने से कई बार लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है. लेकिन सबको इस तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं होती. कुछ लोगों को हम सिर्फ ग्रूम करते हैं. ताकि वो जब पब्लिक इवेंट पर जाए, तब खुद को लेकर उनमें कॉन्फिडेंस हो. इस ग्रूमिंग सेशन में हम उनकी पूरी पर्सनालिटी पर काम करते हैं, ताकि उनकी पर्सनालिटी में ओवरऑल फर्क नजर आए.

एक्टर्स से पॉलिटिशियन तक, सभी के साथ किया है काम

शगुन गुप्ता का मानना है कि अब सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि पुरुष भी अपने चेहरे और शरीर पर ध्यान देने लगे हैं. क्योंकि आज-कल हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, इसलिए अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. शगुन गुप्ता ने एक्टर्स से पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन तक, सभी के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि डॉक्टर-पेशेंट कॉन्फिडेंशिअलिटी के चलते वो उनके नाम का खुलासा नहीं कर सकतीं.

चुनावों में दिव्यांगों को आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने संसद, विधान सभाओं और ग्राम पंचायतों के चुनावों में दिव्यांगों के लिए दो फीसदी आरक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट इस संबंध में दिशानिर्देश कैसे जारी कर सकती है, ये नीतिगत मामला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आप रोजगार में आरक्षण की मांग कर रहे होते तो हम विचार भी कर सकते थे, लेकिन इस मामले में दिशानिर्देश कैसे दे सकते हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 8 नवंबर 2024 के उस आदेश का हवाला दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा कि अगर दिव्यांगों को सार्वजनिक दफ्तरों में पहुंच की व्यवस्था में कोई समस्या है तो हम विचार कर सकते हैं। अगर सार्वजनिक दफ्तरों में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट या रैंप की जरुरत हो तो हम विचार कर सकते हैं।

जस्टिस वर्मा को न सौंपा जाए कोई न्यायिक कार्य

नई दिल्ली

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से 14 मार्च को नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया था जिसने अपनी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आज ही राष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के बाद चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का आदेश दिया। इसके पहले चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे जस्टिस वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले लें। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक काम समेत प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी वापस ले लिया था।

रेडिक्स अकाडेमी द्वारा 23 मार्च भव्य इवेंट का आयोजन

दिव्या दिल्ली: मिडनाइट फूडपार्क में हाल ही में एक शानदार इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी स्टार रितु शिवपुरी ने भाग लिया। इस इवेंट को और भी खास बनाने के लिए रितु शिवपुरी ने अपने गरिमामयी उपस्थिती से इसे और भी रंगीन बना दिया। इवेंट के दौरान रितु शिवपुरी ने विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड्स से सम्मानित किया, और उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए इस इवेंट को एक नई ऊंचाई दी। इस इवेंट का एक प्रमुख आकर्षण था बच्चों का डांस कंपटीशन, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कंपटीशन में 9 साल की जुषा वोरा ने अपनी शानदार डांस पर्फॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया और प्रथम विजेता के रूप में पुरस्कार प्राप्त किया।

"इवेंट के आयोजक विक्की शर्मा ने बताया कि यह उनका 27वां सफल इवेंट था, और वे इस सफलता को अपने समर्थकों और सभी सहयोगियों को समर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस इवेंट को सफल बनाने में नवजीवन सहकारी बैंक का भरपूर सहयोग रहा, जिसके बिना यह आयोजन संभव नहीं होता"

इवेंट के आयोजक विक्की शर्मा ने बताया कि यह उनका 27वां सफल इवेंट था, और वे इस सफलता को अपने समर्थकों और सभी सहयोगियों को समर्पित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस इवेंट को सफल बनाने में नवजीवन सहकारी बैंक का भरपूर सहयोग रहा, जिसके बिना यह आयोजन संभव नहीं होता। इवेंट के दौरान, ग्लिट्ज आइकॉन अवार्ड के अंतर्गत फिल्म स्टार रितु शिवपुरी ने बेस्ट आर्किटेक्ट तुषार गज्जर को विशेष सम्मान से नवाजा। इसके अलावा, कई मेकअप आर्टिस्ट्स और बैंक कर्मियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह इवेंट न केवल एक मनोरंजन का साधन था, बल्कि विभिन्न पेशेवरों और कला क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए सम्मान देने का एक मंच भी था। इस इवेंट ने सभी उपस्थित लोगों को एक प्रेरणा दी और यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण के साथ कोई भी कार्य सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।

पॉलिसीधारकों की सहायता के लिए सप्ताहांत और ईद पर खुले रहेंगे एलआईसी कार्यालय

नई दिल्ली/मुंबई

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रभागों में उसके कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च, 2025 को खुले रहेंगे। एलआईसी ने जारी एक बयान में कहा, "पॉलिसीधारकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए 29, 30 और 31 मार्च को जोनल और डिवीजनों के अधिकार क्षेत्र के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय आधिकारिक कार्य समय के अनुसार सामान्य परिचालन के लिए खुले रहेंगे।" कंपनी ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य सुचारू संचालन

सुनिश्चित करना और पॉलिसीधारकों को असुविधा से बचाना है। कंपनी ने यह कदम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा 12 मार्च को जारी की गई सलाह के बाद उठाया है। दरअसल एलआईसी देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है। एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ सिद्धार्थ मोहंती ने हाल ही में दोहराया कि कंपनी का फोकस ग्रामीण और खासकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती बीमा उपलब्ध कराने पर है।

वन नेशन-वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली

वन नेशन-वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं पाली (राजस्थान) से सांसद पीपी चौधरी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सांसद चौधरी ने इस शिष्टाचार भेंट में प्रधानमंत्री मोदी को एक राष्ट्र-एक चुनाव (वन नेशन-वन इलेक्शन) जेपीसी द्वारा ली गई बैठकों की संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की पारंपरिक लघु चित्रकला की एक विशेष तस्वीर भेंट की। इस तस्वीर को मां चामुण्डा सेल्फ ग्रुप द्वारा बनाया गया, जोकि आदिवासी भील समाज की महिलाओं का

समूह है। प्रधानमंत्री मोदी से हुई भेंट की तस्वीर को सांसद चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर साझा करते हुए इसे भावुक क्षण बताया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाया है और सभी क्षेत्रों में विकास को नई गति दी है।

हमेशा की तरह, आपने गर्मजोशी एवं स्नेह दिखाया और राष्ट्रसेवा का अमूल्य मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी से मिलकर हृदय भावुक हुआ। आपके उदात्त सानिध्य में विकसित भारत निर्माण के लिए काम करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय की गहराईयों से आभार। चौधरी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इससे पहले सांसद चौधरी राष्ट्रपति दौपद्री मुर्मु के आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित अल्पाहार कार्यक्रम में भी शामिल हुए।

यूनिसेफ और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलाया हाथ

नई दिल्ली

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और यूनिसेफ युवाह भारत के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इस कोलेबोरेशन का मकसद युवाओं और महिलाओं के कौशल, आर्थिक और सामाजिक अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाना है। इस बारे में जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (रडक) साइन किया गया है। इस तीन साल की पार्टनरशिप के जरिए, यूनिसेफ युवाह और एमओआरडी पहले से राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर चल रही पहलों पर काम करेंगे ताकि कौशल, आर्थिक अवसरों और सामाजिक प्रभाव के लिए स्केलेबल समाधानों का सह-निर्माण किया जा सके, जिसमें कमजोर आबादी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पार्टनरशिप के जरिए मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की एसएचजी महिलाओं और उनके परिवार की महिला सदस्यों (18-29 वर्ष) को नौकरियों, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी टीके अनिल कुमार ने कहा, "यह पार्टनरशिप बहुत ही सही समय पर आई है, क्योंकि यह बजट 2025-26 में घोषित रूरल प्रोस्पेरिटी और रेजिलिएंस प्रोग्राम के मुताबिक है। यह खासतौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 करोड़ एसएचजी सदस्यों में से लगभग एक तिहाई युवा हैं, जो इस पहल में मुख्य भूमिका निभाएंगे।" यूनिसेफ इंडिया की डिप्टी रिप्रेजेंटिव ऑपरेशन्स, शारदा थापलिया ने कहा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कौशल विकास के रास्ते को बढ़ाने और इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने से, इस पार्टशिप में स्थायी आजीविका बनाने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की क्षमता है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में निवेश करना सिर्फ व्यक्तिगत प्रगति ही नहीं है।

बल्कि यह समुदाय और राष्ट्रीय स्तर पर विकास को भी बढ़ावा देने के बारे में है।

यह पहल युवा हब जैसी नवीन सुविधाओं को एकीकृत करेगा, जो नौकरियों, कौशल और वॉलंटियरिंग के लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है।

भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए 191.736 अरब जापानी येन ऋण समझौतों पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली

भारत और जापान ने आधिकारिक विकास सहायता के तहत छह परियोजनाओं के लिए 191.736 अरब जापानी येन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजनाएं वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन के क्षेत्रों से संबंधित हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत और जापान ने गुरुवार को वन

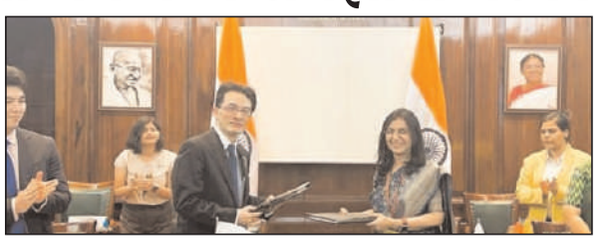

प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलकृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन के क्षेत्रों में जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के अंतर्गत छह परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच नई दिल्ली में इन छह ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें "तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम (चरण 3) (टीएनआईपीपी-)" (36.114 बिलियन जेपीवाई), "प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता वृद्धि के लिए परियोजना (8.280 बिलियन जेपीवाई), " और "पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परियोजना" (11.480 बिलियन जेपीवाई) है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 658.8 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली/मुंबई

अर्थयवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। लगातार तीसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा दर्ज हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 मार्च को समाप्त हफ्ते में 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 658.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 30.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 654.27 अरब डॉलर हो गया था। आरबीआई ने शुक्रवार को आंकड़ों में बताया कि 21 मार्च को समाप्त हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 658.8 अरब डॉलर रहा है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 30.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 654.27 अरब डॉलर हो गया था। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का अहम घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.67 अरब डॉलर बढ़कर 558.86 अरब डॉलर हो गईं।

सड़क योजना के तहत पिछले एक माह में 4011 करोड़ का केंद्रांश राज्यों को जारी: शिवराज

2612 किलोमीटर लम्बाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग-अलग राज्यों में दी गई

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले एक माह के दौरान 4 हजार 11 करोड़ रुपये का केंद्र का अंश राज्यों को जारी किया गया है। इस दौरान 2612 किलोमीटर लम्बाई की 231 सड़कों और 96 पुलों के निर्माण की स्वीकृति भी अलग-

अलग राज्यों में दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि पुदुचेरी में 108 किलोमीटर लम्बाई की 41 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। पीएम-जनमन योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 508 करोड़ 29 लाख रुपये की 738.99 किलोमीटर की 377 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। इसी दौरान त्रिपुरा को 76 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से लगभग 84 किलोमीटर लम्बाई की 25 सड़कों को स्वीकृति दी गई है। बिहार को 5 सड़कें और 103 पुल दिये गये हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एक सड़क और एक पुल स्वीकृत किया गया है। मंत्री ने बताया कि मणिपुर को 41 सड़कें दी गई हैं। मध्य प्रदेश को 6 पुल स्वीकृत किये गये हैं और आन्ध्र प्रदेश को 338 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये, बिहार को 157 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 185 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 309 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 342 करोड़ रुपये, झारखंड को 445 करोड़ रुपये, लद्दाख को 37 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 165 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 391 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 378 करोड़ रुपये की राशि का केंद्र का अंशदान दिया गया है। शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पर्याप्त सहायता दी जा रही है ताकि गांव भी बारहमासी सड़कों से जुड़ सकें। गरीबों और ग्रामीण भाई-बहनों को उसका लाभ मिल सके।

राणा सांगा के मुद्दे पर राज्यसभा में चौतरफा घिरे सपा सांसद, सदन में मचा हंगामा

नई दिल्ली

सपा नेता रामजी लाल सुमन की राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सांसदों द्वारा कार्यवाही बाधित करने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

क्या था सपा सांसद का बयान

राज्यसभा में सपा सांसद द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ था।

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने भाषण में राणा सांगा को 'गद्दार' करार देते हुए ये दावा किया था कि उन्होंने मुगल बादशाह बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। सपा सांसद के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया था।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397